● वर्ष : 17 ● अंक : 123 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का स्तंभ

दिल्ली से प्रकाशित शुक्रवार 20 फरवरी 2026

प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का किया उद्घाटन

वैष्णव ने की नई दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट प्रतिबद्धताओं की घोषणा

एआई समिट को संबोधित कर मोदी ने दिया बड़ा संदेश- सबकी भलाई और सबकी खुशी हमारा बेंचमार्क

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य पारदर्शिता, जवाबदेही और मानव-हित पर आधारित होना चाहिए। एआई कुछ देशों या कंपनियों का साधन नहीं बने, बल्कि यह "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" का माध्यम बने। प्रधानमंत्री ने एआई के लिए मानव विजन पेश करते हुए कहा कि अवसरों के साथ जोखिम भी हैं, इसलिए इसे मानव-केंद्रित और जिम्मेदार तरीके से विकसित करना जरूरी है। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, वैश्विक तकनीकी कंपनियों के प्रमुख और उद्योग जगत के दिग्गज मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान 'नई दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट प्रतिबद्धताओं' की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य एआई को समावेशी, बहुभाषी और वैश्विक विकास का साधन बनाना है। प्रधानमंत्री ने डीप फेक जैसी चुनौतियों का जिक्र किया और कहा कि जैसे खाने की चीजों पर लेबल लगता है कि उसमें क्या है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी लेबलिंग जरूरी है ताकि लोग सच-झूठ पहचान सकें। इसकी स्पीड और स्केल इतनी बड़ी है कि इसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतनी होगी। एआई को खुली छूट मिलनी चाहिए, लेकिन कमान हमारे हाथ में होनी चाहिए । विकासशील देशों के लिए एआई को लोकतांत्रिक बनाना जरूरी है। मनुष्यों को सिर्फ डेटा का स्रोत नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि एआई को सशक्तिकरण का माध्यम बनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ एआई से डरते हैं, कुछ इसमें भाग्य देखते हैं। भारत गर्व से कहता है कि हमें एआई में भय नहीं, भाग्य और भविष्य दिखता है। भारत सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग तक मजबूत इकोसिस्टम बना रहा है। सुरक्षित डेटा सेंटर, मजबूत आईटी ढांचा और डायनामिक स्टार्टअप कल्चर भारत को किफायती, स्केलेबल और सुरक्षित एआई का हब बना सकता है। भारत की विविधता, युवा आबादी और लोकतंत्र इसे खास बनाते हैं। यहां सफल एआई मॉडल पूरी दुनिया में काम कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे स्कूल का सिलेबस बच्चों के लिए सुरक्षित और परिवार के मार्गदर्शन में होता है, वैसे ही एआई भी बच्चों के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल्स और ऐप्स लॉन्च किए, जो युवाओं की प्रतिभा और भारत की विविधता को दिखाते हैं।

एआई समिट में एंटोनियो गुटेरेस, मुकेश अंबानी और एन. चंद्रशेखरन ने भारत पर जताया भरोसा

नई दिल्ली। भारत के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी, टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और अमेरिकी एआई कंपनी एन्थ्रोपिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डारियो अमोदेई सहित दुनिया के शीर्ष लोगों और उद्योग जगत के दिग्गजों ने भारत की एआई नेतृत्व क्षमता की खुलकर सराहना की। इन लोगों ने कहा कि भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा, जनसंख्या और नवाचार के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी एआई शक्ति बनने की स्थिति में है। भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में एआई को प्रमुख ताकत बनाएगा। साथ ही वैश्विक दक्षिण के लिए भी भारत एआई विकास का मॉडल बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यहां भारत मंडपम में समिट के दौरान आयोजित सत्र में कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस समिट के आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण में इस तरह के पहले एआई समिट की मेजबानी करके भारत ने नेतृत्व दिखाया है। एआई का भविष्य कुछ देशों या कुछ अरबपतियों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। यह पूरी मानवता से जुड़ा विषय है। इसमें सभी देशों की भागीदारी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स के तहत अग्रणी एआई कंपनियां और भारतीय नवाचारकर्ता मिलकर जिम्मेदार एआई के लिए स्वैच्छिक संकल्प कर रहे हैं।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

एआई समिट की चमक और ज़मीनी हकीकत

भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को लेकर बड़े-बड़े दावे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। सरकार ने पिछले वर्ष एआई विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया था, खबरों के अनुसार उसमें से लगभग 800 करोड़ रुपये ही खर्च हो सके। यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि नीति और क्रियान्वयन के बीच की दूरी को दर्शाता है। जब देश में एआई समिट का आयोजन किया जा रहा है। मंचों से डिजिटल क्रांति की बात हो रही है। तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है, सरकार की इस मामले में वास्तविक सोच क्या है? सरकार ने एआई में शोध के लिए किस तरह की नीतियां बनाई हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेज में शोध के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। इस दौड़ में कैसे भारत आगे रहेगा। इसकी कोई वास्तविक सोच दिख नहीं रही है। एआई को लेकर भारत सरकार भी सपने देख रही है और वही सपना लोगों को दिखा रही है। विश्वविद्यालयों और आईटी सेक्टर को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

शोध के लिए पिछले कई वर्षों में केंद्र सरकार को बजट में जो धन उपलब्ध कराना था, उसे बढ़ाने के स्थान पर और कम किया है। शोध संस्थानों में बुनियादी ढांचा, उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग संसाधन और दीर्घकालिक अनुदान की कमी होने के कारण शोध लगभग लगभग बंद हो गए हैं। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को पर्याप्त प्रोत्साहन नही मिलेगा, तो स्वदेशी एआई तकनीक के साथ कदमताल कर पाना संभव नहीं होगा। भारत एक बाजार बनेगा। जहां पर विदेश से आयातित उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे और हम बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा और रोजगार के अवसर विदेशों को देने का काम करेंगे। एआई समिट में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी स्वागत योग्य है। भारत सरकार यदि भारत को एक उपभोक्ता बाजार बनाना चाहती है तो यह भारत सरकार की सोच है। भारत सरकार विदेशी कंपनियों के लिए पलक पावड़े बिछाती है। भारतीय कंपनियों और भारतीय शोधकर्ताओं के ऊपर सरकार को विश्वास ही नहीं है। सरकार जो नीतियां बनाती है उनके क्रियान्वयन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है, कि भारतीय शोधकर्ता और भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के मुकाबले में पिछड जाती हैं।

यह स्थिति दीर्घकालिक दृष्टि से बहुत चिंताजनक है। दुनिया की अग्रणी कंपनियां जैसे ओपन एआई, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों को भारतीय राजनेता और भारतीय नौकरशाह दामाद की तरह स्वागत करते हैं। भारत सरकार का हर काम इन्हीं कंपनियों को सौंपा जाता है। इनसे अच्छे उत्पादन यदि भारतीय कंपनियों और सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार करते हैं। उन्हें सरकार कोई तवज्जो नहीं देती है, जिसके कारण वह विदेशो में जाकर अपना करियर बनाने के लिए विवश होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला एवं अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों के साथ सरकारी संरक्षण को लेकर भारतीय एवं वैश्विक बाजार में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.**9911371802**
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER**786**@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

गूगल पांच साल में करीब 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का करेगी निवेश

नई दिल्ली। एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में भारत को विदेशी कंपनियों से ढेरों निवेश मिले हैं, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और क्वालकॉम जैसी कंपनियां शामिल हैं। समिट में कंपनियों ने बताया है कि वे भारत में डेटा सेंटर्स और न्यू एआई मॉडल को डेवलप करेंगे। बुधवार को गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से मुलाकात की और बताया कि कंपनी अगले पांच साल में भारत में करीब 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। समिट में गूगल सीईओ और गूगल डीपमाइंड जीफ डेमिस हासाबिस दोनों भारत में हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गूगल का निवेश देश के पहले बड़े एआई हब को तैयार करेगा। प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा आंध्रप्रदेश के विशाखापत्तनम में बनने वाला मेगा एआई डेटा सेंटर है। इसमें एआई मॉडल ट्रेनिंग, क्लाउड सर्विस और कंप्यूटिंग का केंद्र बनेगा। एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में माइक्रोसॉफ्ट ने बुधवार को ऐलान किया है कि वह ग्लोबल साउथ में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। यह निवेश आने वाले चार साल के दौरान की जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ने बीते साल भारत में 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का ऐलान किया था। योट्टा डेटा सर्विसेज ने भी ऐलान किया है कि वह एनवीडिया के लेटेस्ट चिप्स के डेवलपमेंट पर 2 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश करेंगे।

गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ शीर्ष नेताओं दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक, महान समाज सुधारक और शिक्षाविद गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ शीर्ष नेताओं ने नमन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि पर नमन करते हुए कहा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने आजादी के आंदोलन से युवाओं को जोड़कर स्वाधीनता के लिए उन्हें प्रेरित किया, वहीं अस्पृश्यता उन्मूलन व समाज सुधार के लिए भी निरंतर कार्य किए। देशहित के विषयों पर गोखले अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक नेता, महान समाज सुधारक, कानूनी राजनीति के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाले गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर नमन किया। किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मां भारती के वीर सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपके ओजस्वी विचार और आदर्श जीवन सदैव हमें राष्ट्र की सेवा व जनकल्याण हेतु प्रेरित करते रहेंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरीराज सिंह ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

फ्रीबीज बांट रहे राज्यों पर नाराज हुए सीजेआई, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की जगह रोजगार दें

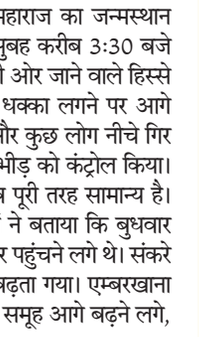

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने चुनाव के दौरान फ्रीबीज बांट रहे राज्यों को कड़ी फटकार लगा दी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि आखिर करदाता के अलावा इन योजनाओं का खर्च और कौन उठाने वाला है। उन्होंने कहा कि भोजन और बिजली के बाद अब सीधा कैश ट्रांसफर होने लगा है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि देश में केंद्र और राज्यों सरकार को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास पर अब कम खर्च किया जा रहा है। दरअसल सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कर्ज के बाद भी राज्यों की तरफ से मुफ्त में चीजें बांटने पर चिंता जाहिर कर दी। उन्होंने सवाल किया, आखिर करदाता नहीं, तब इन योजनाओं के लिए भुगतान कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने नकद बांटने और मुफ्त की सुविधाएं देने को लेकर वित्तीय समझदारी पर भी सवाल उठाए हैं। सीजेआई का कहना है कि राज्यों को मुफ्त की रेवड़ियां या डोल्स बांटने के बजाय रोजगार पैदा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। सीजेआई ने चेताया है कि विकास पर अब कम खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा, अगर आप मुफ्त खाना..., मुफ्त साइकिल...,मुफ्त बिजली देते... और अब तक सीधा कैश ट्रांसफर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा है कि कई राज्य राजस्व घाटे का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किए हुए हैं। कोर्ट का मानना है कि कर्मचारियों के वेतन और मुफ्त की सुविधाओं का बोझ इतना बढ़ गया है कि वे विकास के लिए जरूरी फंड को खत्म कर रहे हैं।

वैश्विक समुदाय समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए आपस में हाथ मिलाए : राजनाथ सिंह

एजेंसी। नई दिल्ली

विशाखापत्तनम के पूर्वी तट पर चल रहे बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 'मिलन' में 74 देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं, ताकि समुद्री जुड़ाव, सामूहिक सुरक्षा और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। अभ्यास का औपचारिक उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज के कानूनी ढांचे को एक बड़े ग्लोबल नेवल आर्किटेक्चर के जरिए और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय नियमों और नेविगेशन की आजादी पर आधारित समुद्री व्यवस्था बनाना चाहता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक भरोसेमंद विश्व-मित्र है, इस क्षेत्र में एक कंस्ट्रक्टिव और भरोसेमंद भूमिका निभाता रहेगा । उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे समुद्र में उभरती हुई मुश्किल और आपस में जुड़ी चुनौतियों से असरदार तरीके से निपटें और आपसी सम्मान और लेन-देन की भावना से काम करें। समय के साथ इंटरनेशनल शांति बनाने में नौसेना की भूमिका और बढ़ी है। पिछले कुछ दशकों में तेजी से आर्थिक विकास हुआ है, जिससे इंटरनेशनल व्यापार और ट्रांसपोर्ट में भारी बढ़ोतरी हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे पानी को उन खतरनाक आतंकवादी गतिविधियों से बचाने की जरूरत है, जो इन इलाकों में पैर पसार रही हैं। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि पुराने खतरे, पाइरेसी, समुद्री आतंकवाद, गैर-कानूनी मछली पकड़ना, ट्रैफिकिंग, साइबर कमजोरियां और जरूरी सप्लाई चेन में रुकावट जैसी नई चुनौतियों के साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ा रहा है, जिससे मानवीय और आपदा राहत ऑपरेशन ज्यादा बार-बार और मुश्किल हो रहे हैं।

शिवाजी महाराज की जयंती कार्यक्रम में मची भगदड़, किले की टूटी रेलिंग, कई घायल

पुणे। पुणे जिले के जुन्नार में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर समारोह में भारी भीड़ के चलते रेलिंग टूट गई। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। एसपी ने बताया कि इस घटना में कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में बताया है। एसपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना शिवनेरी किला परिसर में हुई, जो शिवाजी महाराज का जन्मस्थान माना जाता है। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 3:30 बजे हाथी दरवाजा और गणेश दरवाजा की ओर जाने वाले हिस्से में भीड़ अचानक बढ़ गई। पीछे से धक्का लगने पर आगे खड़े लोगों का संतुलन बिगड़ गया और कुछ लोग नीचे गिर गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत भीड़ को कंट्रोल किया। प्रशासन का कहना है कि स्थिति अब पूरी तरह सामान्य है। रिपोर्ट के मुताबिक वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बुधवार रात से ही बड़ी संख्या में लोग किले पर पहुंचने लगे थे। संकरे प्रवेश और निकास मार्गों पर दबाव बढ़ता गया। एम्बरखाना के नीचे वाले हिस्से में एक साथ कई समूह आगे बढ़ने लगे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

देशभक्ति दिल से होती, कानून बनाकर मजबूर नहीं करना चाहिए : शशि थरुर

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर ने 'वंदे मातरम' को लेकर चल रही बहस पर साफ कहा कि किसी भी नागरिक को गाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। उन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस की आलोचना कर कहा कि देशभक्ति दिल से होती है, और कानून बनाकर इस गाने को जबरन किसी की जुबान पर नहीं लाया जा सकता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश दिए हैं कि राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' अब सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में पूरा गाना अनिवार्य होगा। कांग्रेस नेता थरूर ने इस दौरान 'वंदे मातरम' के इतिहास का उल्लेख किया। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था और स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों और सत्याग्रहियों को प्रेरित करता था। उन्होंने कहा कि आज एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में राज्य और व्यक्तिगत अंतरात्मा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 'वंदे मातरम' गाती थी, लेकिन देश की धार्मिक विविधता को देखकर 'जन गण मन' को राष्ट्रगान चुना गया। संविधान सभा ने 'वंदे मातरम' को राष्ट्रीय गीत का समान दर्जा दिया, ताकि स्वतंत्रता संग्राम में इसकी भूमिका सम्मानित हो और किसी समुदाय को अलग-थलग न किया जाए।

अरुणाचल के करीब परमाणु हथियारों का जाल बिछा रहा चीन, भारत के लिए खतरे की घंटी

एजेंसी। नई दिल्ली

चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की सेना न्यूक्लियर हथियारों के दम पर डराने के पैंतरे आजमा रही है। दुनिया की नजरों से छुपकर चीन के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी, जिसका कच्चा चिट्ठा अब सैटेलाइट तस्वीरों ने खोल दिया है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल करीब परमाणु हथियारों का जाल बिछा रहा है। चीन की यह गुस्ताखी न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे एशिया की शांति के लिए खतरा बन सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश की सीमा से महज 800 किलोमीटर दूर चीन के सिचुआन प्रांत में परमाणु ताकत का विस्तार चल रहा है, जिसका पर्दाफाश सैटेलाइट तस्वीरों ने किया है। इन फोटोज में चीन का वह गुप्त साम्राज्य दिख रहा है जहां न केवल नए परमाणु हथियार बन रहे हैं बल्कि उन्हें और भी घातक बनाने के लिए परीक्षण किया जा रहा है, जहां रूस और अमेरिका के बीच परमाणु संधि खत्म हो चुकी है, दूसरी तरफ चीन का यह बेलगाम परमाणु विस्तार दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। सिचुआन की पहाड़ियों में छिपे ये ठिकाने सीधे तौर पर भारत के पूर्वी इलाकों के लिए रेड अलर्ट हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि सिचुआन की घाटियों में दो प्रमुख जगहों पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।

जीएसटी घटाकर लोगों को दी राहत, लेकिन 6 माह में ही दाम बढ़ा कंपनियों ने कर दी छूमंतर

एजेंसी। नई दिल्ली

तू डाल-डाल, मैं पात-पात.....यह कहावत मोदी सरकार और एफएमसीजी कंपनियों के हालिया समीकरण पर सटीक बैठती है। केंद्र सरकार आम आदमी को राहत दिलाने की कितनी भी कोशिश कयों न कर ले, लेकिन कंपनियों ने ठान रखा है कि हम ऐसा नहीं होने देने वाले है। अभी 4 माह पहले ही केंद्र सरकार ने रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले 200 से भी ज्यादा आइटम पर जीएसटी घटाकर आम आदमी को राहत दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन एफएमसीजी कंपनियों ने इन सभी प्रोडक्ट के दाम बढ़ाकर राहत को एक झटके में छूमंतर कर सरकार की मंशा पर पानी फेर दिया है। दरअसल एफएमसीजी कंपनियों ने तेल, साबुन, टूथपेस्ट सहित तमाम दैनिक उपयोग वाली चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इन एफएमसीजी कंपनियों का कहना है कि लागत में बढ़ोतरी की वजह से इन वस्तुओं के दाम बढ़ाना जरूरी हो गया है। डॉलर के मुकाबले रुपये में आ रही गिरावट से कच्चे माल का आयात महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर उत्पादन लागत पर पड़ रहा है। इसके बाद इन प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी करना मजबूरी हो गया है। वहीं इस पूरे मामले में डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना है कि डिटर्जेंट, हेयर ऑयल से लेकर चॉकलेट, बिस्कुट, नूडल्स, अनाज सहित तमाम रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम बढ़े हैं। इस महीने के आखिर तक इन चीजों के बढ़े दाम वाली पैकेट खुदरा दुकानों पर पहुंच जाएगी और ग्राहकों को भी महंगी कीमत पर सारे सामान खरीदना होगा। जीएसटी कटौती के बाद इन सभी की खपत 6 फीसदी बढ़ गई थी, लेकिन अब फिर से बिक्री पर दबाव पड़ सकता है. डाबर इंडिया के सीईओ ने बताया कि चालू वित्तवर्ष की चौथी तिमाही में वस्तुओं के दाम 2 फीसदी तक बढ़ाए हैं, जो अगले साल भी लागू रहेंगी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के प्रबंध निदेशक ने कहा है कि चाय की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। जनवरी से अप्रैल तक बढ़ोतरी की समीक्षा होगी और उसके बाद आगे कीमतें बढ़ाने पर फैसला किया जाएगा।

रिहाई की मांग को लेकर अटक ब्रिज पर इमरान समर्थकों का कब्जा, मुनीर ने भेजी सेना

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो गए हैं। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के हजारों समर्थकों ने खैबर प्रांत में सामरिक और रणनीतिक रूप से अहम अटक ब्रिज पर बुधवार को कब्जा कर लिया। ब्रिज के दोनों ओर इमरान समर्थकों के जमावड़े के कारण वाहन अटग गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के तेवरों को देखते हुए पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद, पेशावर व रावलपिंडी कैंट से करीब 5 हजार सैनिकों को रवाना किया। उधर, खैबर के सीएम सुहैल अफरीदी ने रिहाई के लिए युवाओं की इमरान रिलीज फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इमरान के समर्थन में तहाफुज पार्टी (टीटीपी) ने भी इस्लामाबाद कूच का ऐलान किया है। इमरान समर्थकों के अटक ब्रिज पर कब्जे से खैबर सूबा से पाक से कट गया है। इससे पाकिस्तान में अफरा-तफरी मच गई। आनन फानन में मुनीर को फौज भेजने का फैसला लेना पड़ा।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEUTICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

ख़ास ख़बर

गोयल ने फिनलैंड के पीएम और स्विस कन्फेडरेशन के अध्यक्ष से मिलकर व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को नई दिल्ली में फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने इंडिया-ईयू व्यापार समझौते से मिलने वाले मौकों पर बात की। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने 'एक्स' पोस्ट पर जारी एक बयान में लिखा, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो से मिलकर सच में बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे भारत-ईयू व्यापार समझौता हमारे देशों को सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसे खास सेक्टर्स में मिलकर काम करने के बड़े मौके देती है, जिससे इंडिया-फिनलैंड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के रिश्ते और मज़बूत होंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने आज स्विस कन्फेडरेशन के अध्यक्ष गाई परमेलिन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में दोनों नेताओं ने भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत भारत-स्विट्जरलैंड कार्यनीतिक सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। परमेलिन इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में भाग लेने के लिए भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। भारत और स्विट्जरलैंड ने इस बैठक में भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के तहत अपनी दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी और कार्यनीतिक सहयोग को और गहरा करने की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इस बैठक में एआई इंपैक्ट समिट के संदर्भ में दोनों पक्षों ने नवाचार और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को स्वीकार किया और कहा कि टीईपीए प्रेसीजन इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, नवाचार और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी सहयोग के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

डीएमआरसी ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदले जाने का किया विरोध

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सर्वोच्च न्यायालय करने की मांग का विरोध करते हुए कहा है कि इससे सार्वजनिक राजस्व पर बोझ बढ़ेगा। डीएमआरसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि अगर ये मांग मानी गयी तो कई दूसरी याचिकाएं दायर की जाएंगी और दिल्ली मेट्रो पर काफी बोझ बढ़ जाएगा। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान डीएमआरसी के वकील ने कहा कि फिलहाल अंग्रेजी और हिंदी में मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। डीएमआरसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो का नाम बदलकर सर्वोच्च न्यायालय करने से सार्वजनिक धन का करीब 40 से 45 लाख रुपये का खर्च होगा। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशनों का नाम बदलना एक नीतिगत फैसला है। डीएमआरसी ने कहा कि अगर एक मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की अनुमति दी जाएगी, तो ऐसी ही कई मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने के लिए याचिकाएं दायर की जाएंगी। तब कोर्ट ने कहा कि कई याचिकाएं दायर होने की आशंका इस मांग को खारिज करने की वजह नहीं हो सकती। उच्च न्यायालय ने 11 फरवरी को याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएमआरसी को नोटिस जारी किया था। याचिका वकील उमेश शर्मा ने दायर किया है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम हिन्दी में सर्वोच्च न्यायालय रखा जाए। याचिका में कहा गया है कि सेंट्रल सेक्रेटेरियट मेट्रो स्टेशन का नाम हिन्दी में केंद्रीय सचिवालय और दिल्ली यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन का नाम हिन्दी में दिल्ली विश्वविद्यालय है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सर्वोच्च न्यायालय रखा जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर इसका हिन्दी में नाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। याचिका में कहा गया है कि आफिशियल लैंग्वेज एक्ट और उसके नियम के मुताबिक केंद्रीय विभागों के सभी साइन बोर्ड अंग्रेजी और हिन्दी में होने चाहिए। हिन्दी में नाम देवनागरी लिपि में लिखा होना चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने दिल्ली मेट्रो को मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट रखने का सुझाव भेजा और वो मेट्रो प्रशासन के पैनल की ओर से स्वीकार कर लिया गया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि हिन्दी में अनुवाद करने में विभाग काफी आलसी हैं। वे गृह मंत्रालय जा सकते थे। एक राजभाषा विभाग भी है। अगर उन्हें कोई समस्या है तो वे इसका अनुवाद करा सकते थे, लेकिन वे हिन्दी भाषा को खराब कर रहे हैं।

धोखाधड़ी मामले में फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी को मिली जमानत

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 44 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े के मामले में उदयपुर जेल में बंद फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट ने 13 फरवरी को श्वेतांबरी भट्ट को अंतरिम जमानत दी थी। इस मामले में शिकायतकर्ता अजय मुर्दिया के वकील ने कहा कि ये मामला 44 करोड़ के फर्जीवाड़े का है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर निरस्त करने की याचिका नहीं दाखिल की है। इसमें राजस्थान में केस कैसे बना। कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता इंदिरा आईवीएफ के मालिक अजय मुर्दिया को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता चाहता था कि उसके ऊपर फिल्म बने। दोनों फिल्म फ्लॉप हो गयी। इसमें विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी का भला क्या दोष। फिर उन्हें हिरासत में क्यों रखा जा रहा है।

मुफ्त बिजली के वादे पर टीएनपीडीसीएल को फटकार, केंद्र सरकार को नोटिस

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। तमिलनाडु से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर राज्य सरकारें मुफ्त खाना, मुफ्त साइकिल, मुफ्त बिजली और सीधे कैश ट्रांसफर देती रहेंगी तो विकास के कामों के लिए पैसा कहां से आएगा। कई राज्य ऐसे हैं, जो पहले से ही घाटे में हैं, फिर भी वे नई-नई कल्याण योजनाएं शुरू कर रहे हैं। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, लेकिन तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड (टीएनपीडीसीएल) को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उपभोक्ता की वित्तीय स्थिति पर गौर किए बिना हर किसी को मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया। दरअसल, उच्चतम न्यायालय तमिलनाडु पावर डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से दायर बिजली संशोधन कानून के नियम 23 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यह नियम बिजली की कीमतों को नियंत्रित करता है। तमिलनाडु पावर डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड ने इसे राज्य के कामकाज में दखल और लोगों के कल्याण के लिए शुरु की गई योजना के विरुद्ध बताया। कोर्ट ने कहा कि हम देश में कैसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं जो लोग बिजली का बिल चुकाने में असमर्थ हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजना होनी चाहिए। सबको मुफ्त सुविधा क्यों दी जाए। कोर्ट ने डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजनाओं पर भी सवाल उठाया और कहा कि राज्य का कर्तव्य रोजगार के अवसर पैदा करना है।

कृषि मंत्रालय के सभी कार्यक्रमों की शुरुआत अब पौधरोपण के साथ की जाएगी: शिवराज

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि मंत्रालय के सारे कार्यक्रम अब से पौधरोपण के साथ शुरू किए जाएंगे। कृषि विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में पहले पेड़ लगाए जाएंगे और विद्यार्थियों से संकल्प दिलवाया जाएगा कि वे जीवनभर अपने जन्मदिन पर पौधा लगाएंगे। केवीके, एग्रीकल्चर कॉलेज और रिसर्च से जुड़े किसी भी आयोजन में पेड़ लगाना शुरुआती अनिवार्य कदम होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज गुरुवार को "एक पौधा प्रति दिन" संकल्प के पांच वर्ष पूर्ण होने पर पूसा स्थित एपी शिंदे हॉल में आयोजित विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर साध्वी ऋतंभरा और पर्यावरणविद् डॉ. अनिल जोशी, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट, साधना सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमरकंटक में 19 फरवरी 2021 के दिन नर्मदा तट पर "रूद्राक्ष" और "साल" के पौधे रोपकर नर्मदा सेवा यात्रा के समापन पर मध्य प्रदेश में 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए, जिसने नदी, जंगल और जलवायु संरक्षण को जनआंदोलन में बदल दिया। इसी क्रम में "अंकुर अभियान" शुरू किया गया, जिसमें नागरिकों को पौधा लगाकर उसकी फोटो/सेल्फी पोर्टल पर अपलोड करने और उसकी रक्षा का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस अभियान के माध्यम से लगभग 1 करोड़ पौधे लगाए गए। उन्होंने सुझाव दिया कि एक राष्ट्रीय मंच बनाया जाए, जिसका नाम "संभावना" या "अंकुर" हो सकता है, जहां नागरिक जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, बच्चों की वर्षगांठ, किसी प्रियजन की जयंती या पुण्यतिथि पर पौधा लगाने या लगवाने के लिए पंजीकरण कर सकें। महानगरों में रहने वाले लोग तय राशि (जैसे 100–150 रुपये) देकर अपने नाम से पेड़ लगवा सकें, और बदले में उन्हें उस पेड़ की फोटो और स्थान की जानकारी भेजी जाए। उन्होंने कहा कि देश में दानदाताओं की कोई कमी नहीं, कमी केवल काम करने वाले हाथों और व्यवस्थित मंच की है। यदि यह व्यवस्था खड़ी हो जाए तो "एक पौधा प्रति दिन" जैसे संकल्प एक महाअभियान में रूपांतरित हो सकते हैं। साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि पौधरोपण धर्म, संस्कृति और धरती- तीनों की रक्षा का सच्चा यज्ञ है। पेड़ केवल हरियाली नहीं बल्कि धर्म, संस्कृति और धरती– तीनों की रक्षा का माध्यम हैं। पेड़ हमारे शास्त्रीय प्रतीकों, देववृक्षों और मातृभूमि की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। जब कोई व्यक्ति या परिवार जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, गृहप्रवेश या अन्य शुभ अवसरों पर पौधा लगाता है, तो वह केवल पेड़ नहीं, बल्कि पीढ़ियों के लिए पुण्य व संरक्षण का बीज भी बोता है। उन्होंने भावपूर्ण अपील की कि दिखावटी खर्च, आतिशबाजी और क्षणिक उत्सवों की बजाय लोग अपने शुभ अवसरों पर पौधारोपण को "सच्चा यज्ञ" मानें और हर पौधे की रक्षा को वैसा ही धर्म समझें जैसा हम मंदिर में दिए व्रतों का पालन करते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय में 'गीता के माध्यम से नेतृत्व उत्कृष्टता' विषयक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

गीता केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं है बल्कि आधुनिक नेतृत्व और प्रबंधन की अवधारणाओं की प्रभावी व्याख्या करने वाला दार्शनिक ग्रंथ है-प्रो. निरंजन कुमार

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय की मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम समिति द्वारा 'गीता के माध्यम से नेतृत्व उत्कृष्टता' विषय पर दो दिवसीय 16-17 फरवरी को क्षमता संवर्धन कार्यशाला (कैपिसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप) का आयोजन किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए आयोजित इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम समिति के अध्यक्ष प्रो. निरंजन कुमार ने बताया कि आज के वैज्ञानिक युग में दिल्ली विश्वविद्यालय की मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम समिति द्वारा गीता जैसे धर्म ग्रंथ पर चार कोर्सेस बनाए गए हैं।पाठ्यक्रम निर्माण पर चर्चा करते हुए प्रो.निरंजन ने आगे कहा कि 'गीता केवल धार्मिक ग्रन्थ नहीं है;बल्कि आधुनिक नेतृत्व और प्रबंधन की अवधारणाओं की प्रभावी व्याख्या करने वाला दार्शनिक ग्रंथ है'।उन्होंने बताया कि भारत के पहले गवर्नर-जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर जर्मनी के विल्हेल्म हम्बोल्ट और शोपेनहावर, अमेरिका के राल्फ इमर्सन और हेनरी डेविड थोरो और इंग्लैंड के एल्डस हक्सले आदि अनेक दार्शनिक गीता की दार्शनिक उत्कृष्टता, सार्वभौमिक अपील और आध्यात्मिक गहनता से अत्यंत प्रभावित थे। प्रो. निरंजन ने कहा कि आज इन्टरनेट और एआई के समय में जहाँ सामूहिकता खत्म होती जा रही है ऐसे में गीता हमें स्व से पर की ओर अर्थात् मनुष्यता की ओर ले जाती है। प्रो. कुमार ने कहा कि मूल रूप से हमारे भीतर एक पशु बैठा होता है जो तामसिक होता है, और गीता हमें उस तमोगुण से सतोगुण की ओर लेकर जाती है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्माण बच्चों के जीवन को सही दिशा देने में सहायक सिद्ध होंगे।

जमाअत के अध्यक्ष ने अपने रमज़ान संदेश में गहरी पवित्रता और दृढ़ता का आह्वान किया

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने अपने संदेश में कहा कि इस वर्ष मुसलमान रमज़ान को आंतरिक सुधार और सिद्धांतों वाली ज़िंदगी के एक संजीदा परियोजना के तौर पर देखें। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे समय में जब ईमान और उसूलों पर लगातार दबाव पड़ रहे हैं हमारे रोज़ा रखने का मकसद नेकदिली, सब्र और नैतिक ताकत बढ़ाना है। मीडिया को जारी एक बयान में उन्होंने कहा, "ईश्वर से भक्ति दिल की एक स्थिति है अल्लाह की मौजूदगी और उसकी निगरानी का गहरा एहसास, जो गुनाहों के प्रति हिचकिचाहट और अच्छाई की ओर एक स्वाभाविक आकर्षण पैदा करता है।" उन्होंने कहा कि रोज़ा आस्तिकों को रस्मों और बाहरी डिसिप्लिन से परे जागृति के साथ जीना सिखाता है। रोज़े आध्यात्मिक पहलू पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि रोज़े से इंसान शारीरिक खुशियों के बजाय आध्यात्मिक खुशियों से जान-पहचान करता है, और भूख और नियंत्रण से पता चलता है कि शरीर का आराम सार्थक जीवन को परिभाषित नहीं करता। उन्होंने आगे कहा कि पश्चाताप और क्षमा मांगने से आत्मा स्वच्छ होता है और उद्देश्य को पुनः स्पष्ट करता है वापस लाता है।

32,000 करोड़ के मिशन के साथ भारत करेगा वैश्विक क्रिटिकल मिनरल्स यात्रा का नेतृत्व

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली : श्री जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री, भारत सरकार ने आज क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में संसाधन निर्भरता से मूल्य संवर्धन की दिशा में निर्णायक बदलाव का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत अपने रणनीतिक और आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वैश्विक क्रिटिकल मिनरल्स परिदृश्य में एक आकर्षक और विश्वसनीय गंतव्य के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है। FICCI द्वारा भारत सरकार के खान मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से आयोजित 'इंडियन क्रिटिकल मिनरल्स लैंडस्केपः फाउंडेशन फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर – एम्पावरिंग इनोवेशन, ग्रोथ एंड सेल्फ-रिलायंस' के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत वर्तमान में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए 95 प्रतिशत आयात पर निर्भर है। उन्होंने अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और उन्नत विनिर्माण तक एक सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्र में आयात निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए "रिफॉर्म एक्सप्रेस" मोड में कार्य कर रही है। "केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सभी हितधारकों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में सुधारों को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है," उन्होंने जोर देते हुए कहा।

डॉ. अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशलन स्टडीज (एडीजीआईपीएस) के वार्षिक तकनीकी-सास्कृतिक उत्सव उत्कर्ष 2026 का हुआ भव्य उदघाटन समारोह

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली ! डॉ. अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशलन स्टडीज (एडीजीआईपीएस) के वार्षिक तकनीकी-सास्कृतिक उत्सव उत्कर्ष 2026 का आगाज 19 फरवरी, 2026 से हुआ इस उदघाटन समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. आभा वरमानी, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, (एफिलीएशन ब्रांच) जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली । इस अवसर पर डॉ. विजय धीर डायरेक्टर कॉर्डिनेषन, प्रो. डॉ. निरंजन भट्टाचार्य, डायरेक्टर, श्री बी.एम.के. गुप्ता, डायरेक्टर फाइनान्स, श्रीमती पंखुड़ी अग्रवाल, असिसटेंट डायरेक्टर (एच.आर.) ने इस कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने बताया कि यह बहुत गर्व की बात है कि इस संस्थान के वार्षिक तकनीकी-सास्कृतिक उत्सव उत्कर्ष 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने संस्थान के मैनेजमेंट माननीय चेयरपर्सन श्रीमती अलका दास गुप्ता जी, माननीय अध्यक्ष महोदय श्री विराज सागर दास जी, माननीय उपाध्यक्ष सुश्री सोनाक्षी दास जी और माननीय उपाध्यक्ष श्रीमती देवांषी दास जी के सकुशल मार्गदर्शन की सराहना की तथा अपने संबोधन में बताया कि उन्हें बड़ी खुशी हो रही है कि यह संस्थान के छात्र अलग-अलग क्षेत्रों में जैसे तकनीकी शिक्षा, सफल उद्यमी, यूपीएससी, में अपनी मौजूदगी बनाई और मुझे यह खुशी है कि भविष्य में यह कॉलेज और तरक्की करे। इस संस्थान के निदेशक प्रो. डॉ. निरंजन भट्टाचार्य ने बताया कि मुख्य अतिथि आईपी यूनिवर्सिटी के मानकों को बनाए रखने का आधार है और उनके सकुशल मार्गदर्शन से संस्थान को मद्द मिलती है। इस उत्कर्ष का थीम विरासत से विकास तक है उदाहरण स्वरूप जैसे एक पेड़ को तूफान, आंधी या तेज हवाओं से बचने के लिए मिट्टी में मजबूती से जड़ें जमाकर रहना पड़ता है, उसी तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें भी मजबूत नींव की जरूरत होती है। यदि जड़ें कमजोर हों, तो पेड़ मजबूत होकर खड़ा नहीं रह सकता। उसी तरह हम आम को सिर्फ एक फल के रूप में देखते हैं, लेकिन उसे उगाने और पकाने में पेड़ द्वारा किए गए प्रयास और संघर्ष के बारे में बहुत कम सोचते हैं।" उत्कर्ष 2026 में विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकि, सांस्कृतिक, मिस्टर एंड मिसेस उत्कर्ष 2026, फैशन शॉ, गायन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, नुक्कड नाटक आदि का सफल आयोजन किया जाएगा । 21.02.2026 को स्टार नाइट परफोरमेंस में सुप्रसिद्ध गायिका मिस चारू सेमवाल अपने गानों से समा बाधेंगीं।

भारत में स्थायी चुम्बक का उत्पादन इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा : किशन रेड्डी

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने गुरुवार को कहा कि भारत में इस साल के आखिरी तक दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक (आरईपीएम) का उत्पादन शुरू हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक वाहन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के लिए जरूरी महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम होगा। रेड्डी ने यहां उद्योग मंडल इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (फिक्की) और खान मंत्रालय की ओर से आयोजित सम्मेलन में कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत केंद्र सरकार दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इस क्रम में इसी साल भारत में स्थायी चुंबकों का उत्पादन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत अपने सामरिक और आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ग्लोबल जरूरी खनिज बैंकिंग में खुद को एक आकर्षक गंतव्य के तौर पर स्थापित कर रहा है। भारत अभी जरूरी खनिजों के आयात पर 95 फीसदी निर्भर है। राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के तहत 32,000 करोड़ रुपये के खर्च से काम शुरू हो गया है। रेड्डी ने बताया कि पूरे देश में 4,000 से अधिक क्रिटिकल खनिज अन्वेषण गतिविधियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए सरकार राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट को सपोर्ट कर रही है। रेड्डी ने कहा कि गुजरात सरकार ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है, जबकि आंध्र प्रदेश भी आगे बढ़ने को तैयार है। वह जल्द ही ओडिशा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से भी इन संयंत्रों की स्थापना पर चर्चा करेंगे। यदि पूर्ण मूल्य संवर्धन श्रृंखला विकसित नहीं की गई तो भारत प्रसंस्कृत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्य देशों पर निर्भर बना रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि खान मंत्रालय ने इसके लिए अन्वेषण ब्लॉकों की नीलामी करने के साथ पुनर्चक्रण सुविधाओं को भी मंजूरी दी है। फिलहाल भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त इकाइयों की कमी है और यह एक बड़ी चुनौती है। इसके समाधान के लिए सरकार आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात में महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्र पार्क स्थापित करने की तैयारी में है। उल्लेखनीय है कि दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबक का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन, पवन चक्कियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, वैमानिकी और रक्षा क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है।

सुप्रिया श्रीनेत, अध्यक्ष, सोशल मीडिया & डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा जारी वक्तव्य

लोकतंत्र की शान, जीशान अली

नई दिल्ली: पिछले कुछ दिनों से देश में AI मतलब artificial intelligence की धूम मची हुई है. यह अलग बात है कि हिंदुस्तान की Artificial Intelligence संभावनाओं का दम घोंटने में मोदी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. पहले ट्रेड डील में अमेरिका को अपना सारा डेटा सौंपना और फिर अभी चल रही AI Summit में कुव्यवस्थाओं के बीच, झूठ और चोरी के जो शर्मनाक खुलासे हुए हैं, उन्होंने देश की छवि धूमिल की है लेकिन जो नरेंद्र मोदी AI पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं वो असल में Artificial Intelligence से थरथर काँपते हैं. आपके सामने कुछ तथ्य रख देती हूँ - दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा पिछले 6 हफ़्तों में Indian National Congress के AI से बने 9 वीडियो इस देश के कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी केंद्र और राज्य सरकारों ने डिलीट करवाए हैं मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ - इन सारे वीडियो में क़ानून के तहत जो AI डिस्क्लेमर होना चाहिए वो है. पूरे वीडियो की duration में आपको ऊपर AI GENERATED VIDEO लिखा दिखेगा - जो स्पष्ट करता है कि किसी को भी भ्रमित करने की कोई कोशिश नहीं की गई है

संक्षिप्त समाचार

नारी शक्ति संगठन ने विद्यालय के टैलेंटेड बच्चों को मेडल और चॉकलेट दिए

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहाः हसनपुरः नगर के एक विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी में अपनी प्रतिभा दिखने वाले टैलेंटेड बच्चों को नारी शक्ति संगठन ने विद्यालय के बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए बच्चों को मेडल और चॉकलेट देकर पुरस्कृत किया, इस मौके पर नारी शक्ति संगठन की अध्यक्षा डोली अग्रवाल ने कहा कि विद्यालयों में समय-समय पर ऐसी ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहनी चाहिए इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है तथा बच्चों की प्रतिभा निखर कर सामने आती है, वही उन्होंने बताया कि हमारा संगठन महिलाओं एवं बच्चों के हित में हमेशा तत्पर रहता है तथा समय-समय पर स्कूलों, मंदिरों आदि में सामाजिक कार्य में अपना योगदान देता रहता है, उन्होंने बताया कि हाल ही में भीषण ठंड से बच्चों को राहत दिलाने के लिए नगर के राम मूर्ति पुरुषोत्तम शरण कन्या इंटर कॉलेज के कमरों में कारपेट विछवाया गया था, वही आपको बता दें कि विज्ञान प्रदर्शनी में टैलेंट दिखाने वाले बच्चों को जब संगठन द्वारा चॉकलेट एवं मैडल देकर पुरस्कृत किया गया तो बच्चों के चेहरे पर खुशी झलक उठी, इस मौके पर मुख्य रूप से संगठन की अध्यक्षा डोली अग्रवाल, सीमा, शेफाली, जय सिरोही, अंशु तथा विद्यालय स्टाफ में से शशांक व अंकुश आदि मौजूद रहे।

वन नर्सरी में श्रमिक की मौत से हड़कंप

लोक तंत्र की शान : बिजनौर। बिजनौर के कंडवाश्रम स्थित वन विभाग की नर्सरी में कार्यरत एक दैनिक वन श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हृदय गति रुकना बताया गया है, जबकि परिजनों ने साथी कर्मियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार घटना बुधवार देर रात की है। सुरेंद्र सिंह वन विभाग की नर्सरी में दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत थे और वहीं परिसर में रहते थे। उनके साथ रामगोपाल और महेंद्र सिंह भी तैनात थे। सुरेंद्र सिंह की मौत की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि सुरेंद्र सिंह की हत्या की गई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कुछ परिजन शव को वन विभाग कार्यालय भी ले गए और विरोध जताया। क्षेत्रीय वन अधिकारी महेश गौतम ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हृदय गति रुकने से मृत्यु की पुष्टि हुई है और शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि सुरेंद्र सिंह चलते समय गिर पड़े थे। अधिकारी ने यह भी बताया कि सुरेंद्र सिंह शराब पीने के आदी थे। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अमानगढ़ में हाथी का हमला, बुजुर्ग की मौत

लोक तंत्र की शान : बिजनौर। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सटे रानीनांगल गांव में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। खेत पर बने कच्चे मकान में रह रहे 68 वर्षीय जसवंत सिंह पर एक हाथी ने अचानक हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल है। परिजनों के अनुसार जसवंत सिंह सुबह खेत पर लघुशंका के लिए बाहर निकले थे। उसी दौरान पास में हलचल महसूस हुई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने सामने हाथी को खड़ा देखा। बताया जा रहा है कि उन्होंने हाथी को भगाने की कोशिश की, लेकिन वह आक्रामक हो गया और उन पर हमला कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, मगर तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उन्हें तत्काल नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार में पत्नी और बेटी गहरे सदमे में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हाल के वर्षों में क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही बढ़ी है, जिससे लोग भय के साये में जी रहे हैं। सुबह-शाम खेतों या घरों से बाहर निकलना भी जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से नियमित गश्त और कड़ी निगरानी की मांग की है। रेंज अधिकारी अंकिता किशोर ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजा जाएगा। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई है कि वन्यजीवों की गतिविधि दिखने पर दूरी बनाए रखें और तुरंत विभाग को सूचित करें।

बिजनौर में परिवहन विभाग की पहल

लोक तंत्र की शान : बिजनौर। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बिजनौर ने वाहन स्वामियों को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में 20 और 21 फरवरी 2026 को दो दिवसीय परिवहन मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला उप संभागीय परिवहन कार्यालय परिसर, बिजनौर में प्रतिदिन प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक आयोजित होगा। अधिकारियों के अनुसार मेले का मुख्य उद्देश्य वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्ट संगठनों को एकमुश्त कर (वन टाइम टैक्स) व्यवस्था के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। मेले में दो पहिया मोटर यान, तिपहिया मोटर कैब, ई-रिक्शा, मोटर कैब, मैक्सी कैब, 7500 किलोग्राम तक सकल वाहन भार वाले हल्के भार वाहन तथा उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार संनिर्माण उपस्कर यान और विशेष प्रयोजन यानों के लिए लागू कर प्रावधानों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस दौरान कर निर्धारण की प्रक्रिया, कर की गणना की विधि, भुगतान की प्रक्रिया और निर्धारित समय सीमा के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथ ही वाहन स्वामियों की कर संबंधी समस्याओं का नियमानुसार मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि कर भुगतान एवं समायोजन की सुविधा भी मेले में उपलब्ध रहेगी, जिससे वाहन स्वामियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने जनपद के समस्त वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर मेले का लाभ उठाएं और कर संबंधी अपनी शंकाओं का समाधान कराएं। परिवहन विभाग का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक बनाना है, ताकि वाहन स्वामी समय पर कर अदायगी सुनिश्चित कर सकें।

शराब पीकर लौटा, फिर बिगड़ी तबीयत, हुई मौत

लोक तंत्र की शान : बिजनौर। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के साहनपुर में शराब सेवन के बाद एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम की मांग करते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार साहनपुर पेट्रोल पंप के पास रहने वाले प्रभात पुत्र छोटेलाल की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद मौत हो गई। मृतक मूल रूप से ग्राम उमरपुर मीरा, थाना कोतवाली शहर बिजनौर का निवासी था और अपनी पत्नी कल्पना के साथ साहनपुर में रह रहा था। मृतक के भाई राकेश कुमार ने थाना प्रभारी राहुल कुमार को दी तहरीर में आरोप लगाया कि पारिवारिक क्लेश के बीच प्रभात की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और बिना परिवार को सूचना दिए अंतिम संस्कार का प्रयास किया गया। उनका कहना है कि जब उन्हें जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और चिता की आग बुझाकर पुलिस को सूचना दी।

हसनपुर मे बायपास मार्ग पर घंटो जाम में फंसे रहे वाहन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः गुरुवार को नगर के हसनपुर ब्लॉक तिराहे से अमरोहा, संभल, रहरा बायपास मार्ग पर सुबह से ही जाम की स्थिति बनी रही तथा लोगों को घंटो जाम में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा वही दोपहर के समय जाम की स्थिति उस समय और भी विकराल हो गई जब स्कूलों की छुट्टी होने के बाद दर्जनों स्कूलों की बसें तथा एंबुलेंस आदि भी जाम में फांसी हुई नजर आई, जाम की विकराल स्थिति की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जाम खुलवाया तब जाकर लोगों ने राहत की सास ली, बताया जा रहा है कि जाम की स्थिति इतनी भीषण थी कि वाहन रेंग रेंग कर गुजर रहे थे जिसके चलते लगभग 2 से 3 घंटे तक भीषण जाम से लोगों को दिक्कत हुई वहीं कुछ वाहन चालकों ने हसनपुर के अंदर को अपनी छोटी गाड़ियां डायवर्ट कर दी जिससे शहर के अंदर अंबेडकर पार्क व मुख्य बाजार में भी जाम लगा हुआ नजर आया उधर गुरुवार के चलते नगर के रहरा अड्डे के निकट बृहस्पति बाजार में भारी भीड़ होने के कारण तथा अचानक छोटी गाड़ियों के चार पहिया वाहनों के नगर में प्रवेश करने से भी जाम से लोगों को शहर के अंदर एवं शहर के बाहर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा वहीं पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जाम से लोगों को निजात मिल पाई।

गोमती को स्वच्छ बनाने के लिए आज जुटेंगे दिग्गज

लोक तंत्र की शान

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ "जीवनरेखा का पुनर्जीवनः स्वच्छ गोमती" कार्यक्रम को विशेष रूप से करेंगे संबोधित
- विशेषज्ञों की राय के अनुसार बनाया जाएगा गोमती को स्वच्छ बनाने का रोडमैप

लखनऊ। गोमती नदी को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (एसटीसी) उत्तर प्रदेश शुक्रवार को होटल ताज में कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रूप से शाम 4 बजे संबोधित करेंगे। इस संबंध में एसटीसी के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षत वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम "जीवनरेखा का पुनर्जीवनः स्वच्छ गोमती" में प्रदेश के जलशक्ति और नमामि गंगे मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज शिरकत करेंगे। इस आयोजन के दौरान कई सत्र होंगे। इसमें अनेक विशेषज्ञ गोमती नदी को स्वच्छ बनाने को लेकर अपनी राय रखेंगे। इसी के आधार पर गोमती के जल को बेहतर बनाने का रोडमैप बनाया जाएगा।

रमज़ान का पहला दिनः इबादत से गूँजी मस्जिद काबे साहनी, 'गुनाहों की माफी का महीना' इमाम हैदर अब्बास क़िबला''

लोकतंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

संभल/ संभल पवित्र माह-ए-रमज़ान के आगाज़ के साथ ही क्षेत्र में इबादत और रूहानियत का खास माहौल देखने को मिला। 1 रमज़ान के मौके पर मस्जिद काबे साहनी के इमाम जनाब हैदर अब्बास क़िबला ने नमाज़ियों को खिताब करते हुए फरमाया कि "रमज़ान अल्लाह का महीना है और इस मुबारक महीने में हम सब अल्लाह के मेहमान हैं।" उन्होंने कहा कि जिस तरह कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम उसकी बेहतरीन मेहमाननवाज़ी करते हैं, उसी तरह हमें भी इस मुकद्दस महीने में अपने आमाल को बेहतर बनाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कुरआन-ए-पाक की तिलावत करें, इबादत करें और सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफी मांगें। उन्होंने कहा कि रमज़ान रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना है, जो इंसान को अपनी जिंदगी सुधारने का बेहतरीन मौका देता है। रमज़ान के पहले दिन मस्जिद में नमाज़ियों की भारी भीड़ उमड़ी और मस्जिद खचाखच भरी नजर आई। बच्चों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे जोश व अकीदत के साथ इबादत में शरीक हुए, जिससे माहौल और भी रूहानी हो गया। मस्जिद के मुतवल्ली मौलाना सैयद शबाब नक़वी साहब की सरपरस्ती में बेहतरीन इंतजाम किए गए। साफ-सफाई, अनुशासन और नमाज़ियों की सुविधा का खास ख्याल रखा गया, जिसकी लोगों ने खुलकर सराहना की। वहीं मुन्तज़िर मोमिन रज़ा नक़वी की सक्रिय भूमिका और खिदमत-ए-दीन के जज़्बे की भी तारीफ की गई। उनकी मेहनत से रमज़ान के पहले दिन का आयोजन पूरी तरह कामयाब रहा। रमज़ान के इस मुबारक आगाज़ ने पूरे इलाके में भाईचारे, इबादत और तौबा का खूबसूरत पैगाम दिया।

रहमतों और बरकतों का महीनाः रमज़ान

समाजसेवी व पूर्व चेयरमैन मार्केटिंग संभल, चौधरी मोहम्मद फैज़ान अली का विशेष संदेश

लोकतंत्र की शान

संभल/सिरसी मुक़द्दस माह-ए-रमज़ान का आग़ाज़ होते ही मस्जिदों में रौनक बढ़ जाती है, दिलों में नूर उतरता है और हर मोमिन इबादत की तरफ़ पूरी लगन से रुख़ करता है। यह महीना सिर्फ़ रोज़ा रखने तक सीमित नहीं, बल्कि अपने अंदर तक़वा (परहेज़गारी), सब्र और इंसानियत पैदा करने का महीना है। समाजसेवी व पूर्व चेयरमैन मार्केटिंग संभल, चौधरी मोहम्मद फैज़ान अली ने अपने पैग़ाम में कहा कि रमज़ान हम सबको यह एहसास दिलाता है कि असली कामयाबी दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और नेक किरदार में है। रोज़ा इंसान को भूख-प्यास की तकलीफ़ का एहसास कराता है, ताकि वह ग़रीबों और मजबूरों के दर्द को समझ सके और उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान को चाहिए कि वह इस मुक़द्दस महीने में पाँच वक़्त की नमाज़ की पाबंदी करे, क़ुरआन-ए-पाक की तिलावत करे, ज़कात और सदक़ा अदा करे तथा अपने आस-पास के ज़रूरतमंद लोगों की ख़िदमत को अपनी ज़िम्मेदारी समझे। रमज़ान का असल मक़सद यही है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा करे और अल्लाह से क़रीबी हासिल करे। चौधरी मोहम्मद फैज़ान अली ने आगे कहा कि रोज़ा सिर्फ़ खाने-पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि अपनी ज़बान को झूठ, ग़ीबत और बुराई से रोकने का नाम है; अपनी निगाह को ग़लत चीज़ों से बचाने का नाम है; और अपने दिल को नफ़रत से पाक करने का नाम है। उन्होंने कहा कि रमज़ान हमें आपसी भाईचारे, मोहब्बत और एकता का पैग़ाम देता है। यह महीना समाज में अमन-ओ-अमान और इंसाफ़ की बुनियाद को मज़बूत करने का बेहतरीन मौक़ा है। अगर हम सब इस महीने की रूह को समझ लें, तो हमारा समाज तरक़्क़ी और खुशहाली की राह पर आगे बढ़ सकता है। अंत में चौधरी मोहम्मद फैज़ान अली ने संभल सहित पूरे प्रदेश और देशवासियों को रमज़ान की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए दुआ की कि अल्लाह तआला सबकी इबादतें क़ुबूल फरमाए, गुनाहों को माफ़ करे और मुल्क में अमन, तरक़्क़ी और भाईचारा कायम रखे। रमज़ान हमें सिखाता है—इबादत में सच्चाई, इंसानियत में खिदमत और ज़िंदगी में सादगी। आइए, इस मुक़द्दस महीने को अपने लिए और अपने समाज के लिए बदलाव का जरिया बनाएं।

नेचुरल फॉर्मिंग हब बन रहा यूपीः प्रदेश के सभी 75 जिलों में अब तक 94,300 हेक्टेयर तक पहुंची नेचुरल फॉर्मिंग, योगी सरकार 298 करोड़ रुपये से करेगी विस्तार

लोकतंत्र की शान

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को मिशन मोड में आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। सक्रिय रणनीति बनाकर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में कुल 94,300 हेक्टेयर क्षेत्रफल तक प्राकृतिक खेती का विस्तार किया गया है। यह जल्द ही एक लाख हेक्टेयर तक पहुंचने वाला है।<इस व्यापक अभियान में बुंदेलखंड पर फोकस रखा गया है, जहां विशेष कार्यक्रम के जरिए इसे सफल मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। योगी सरकार रासायनिक निर्भरता कम कर टिकाऊ कृषि व्यवस्था स्थापित करने के लिए नेचुरल फार्मिंग पर विशेष जोर दे रही है।

बुंदेलखंड में 23,500 हेक्टेयर क्षेत्र में गो-आधारित प्राकृतिक खेती-योगी सरकार ने बुंदेलखंड के सभी जनपदों झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट में 23,500 हेक्टेयर क्षेत्र पर गो-आधारित प्राकृतिक खेती का विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर योगी सरकार कृषि को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।

योगी सरकार के फोकस में कम लागत, ज्यादा लाभ वाले कृषि मॉडल-जीवामृत और घनजीवामृत के प्रयोग से रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता घटेगी। इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों की आय बढ़ाने का रास्ता मजबूत होगा। योगी सरकार का फोकस 'कम लागत, ज्यादा लाभ' वाले कृषि मॉडल पर है।

कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए वरदान-गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की संरचना सुधरती है और जलधारण क्षमता बढ़ती है। बुंदेलखंड के साथ ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह पहल खेती को अधिक टिकाऊ बनाएगी। यह कदम क्षेत्रीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है।

गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए इंडियन ऑयल करेगा 60 करोड़ का सहयोग

लोकतंत्र की शान

लखनऊः- गोरखपुर में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 60 करोड़ का सहयोग प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच इस संबंध में एमओयू पर हस्ताक्षर सम्पन्न हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह स्टेडियम केवल एक खेल संरचना नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की उभरती प्रतिभा को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम से क्षेत्र में खेल पर्यटन, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इंडियन ऑयल के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि सार्वजनिक-निजी सहभागिता का यह मॉडल राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण में सीएसआर के माध्यम से सहयोग प्रदान करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वाराणसी में भी एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माणाधीन है, जिसे जून 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। वहीं, गोरखपुर क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया मूवमेंट' जैसे अभियानों के माध्यम से खेल भावना और फिटनेस की संस्कृति को नई दिशा दी है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष के बजट में राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडल में स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त, मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी तीव्र गति से प्रगति पर है।

महेश्वरी महिला मंडल के नए सत्र की प्रथम मीटिंग में चार नये सदस्यों का फूलों के गुलदस्ते से हुआ स्वागत

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

अमरोहाः श्री माहेश्वरी महिला मंडल अमरोहा के नए सत्र की प्रथम मीटिंग बुधवार को हुई। जिसमें स्वास्थ्य और त्वचा देखभाल पर विशेष बैठक आयोजित की गई। मीटिंग का आरंभ अध्यक्ष योगेश मालीवाल, सचिव वर्षा माहेश्वरी एंव वरिष्ठ सदस्य श्रीमती प्रभा मुंद्रा ने दीप प्रज्वलन करके किया। उसके बाद मंडल की सभी सदस्यों ने महेश वंदना की। मंडल में शामिल चार नए सदस्य श्रीमती कविता माहेश्वरी, श्रीमती शालिनी माहेश्वरी, श्रीमती मेघा माहेश्वरी एवं पूजा माहेश्वरी ने शपथ ली सभी नये सदस्यों का फूलों के गुलदस्ते देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में होली के कार्यक्रम किस प्रकार किए जाएं उस पर चर्चा की गई। सभी सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखें इस अवसर पर बदलते मौसम मे त्वचा की देखभाल किस प्रकार की जाए पर एक वार्ता रखी गई। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। जिसमें श्रीमती नीता लड्ढा , नविता मालीवाल, निधि खटोड़, गुंजन मुंदडा पूजा मुंदडा,सोनी काबरा आदि सदस्यों ने भाग लिया। सभी ने त्वचा की देखभाल संबंधी बहुत सारी जानकारियां दी। सदस्यों ने मनोरंजन के लिए हाऊजी खेली और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुफ्त उठाया । इस अवसर पर योगेश मालीवाल, वर्षा माहेश्वरी, शिल्पा माहेश्वरी, नबिता, नीता माहेश्वरी, नीता लड्ढा ,दीपा माहेश्वरी, विनीता माहेश्वरी, प्रीति मालीवाल, सोनी, पूजा, गुंजन ,शुची, शालिनी, शालू , प्रभा ,निधि, रश्मि ,कविता निधि माहेश्वरी दीपा, वीना आदि सदस्य उपस्थित रहे।

झूठी f i R पर सख्ती थानों में लगेगे बोर्ड

- एफआईआर...चेतावनी के बोर्ड थानों में लगाए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट मे भी याचिका दायर हुई शासन से पुलिस को भी पत्र आया

लोक तंत्र की शान, (खिज्र अहमद) नजीबाबाद

नजीबाबादः झूठी शिकायत और झूठी एफआईआर दर्ज कराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही चेतावनी के बोर्ड थानों में लगाए जाने के संबंध पुलिस प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी किए गए है! आदर्श नगर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता मनोज शर्मा ने पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी एक शिकायती पत्र में अवगत कराया था कि वर्तमान में झूठी शिकायतों, झूठी एफआईआर और सोशल मीडिया पर झूठ लिखने का प्रचलन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है आरटीआई कार्यकर्ता ने इस संबंध में झूठी शिकायत पर प्रत्येक थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के बोर्ड लगाए जाने की मांग की थी ताकि आमजन को अपने अधिकार पता चल सके क्योंकि वर्तमान मे झूठी शिकायत,झूठे आरोप प्रत्याआरोप लगाने वाले बाज नहीं आ रहे है अत ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई आवश्यक है इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों को भी पत्र लिखा गया था जिसके परिपेक्ष मे शासन द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय को लिखा गया है उधर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने भी सर्वोच्च न्यायालय मे भी एक याचिका दायर की है ताकि विभिन्न राज्यों के विभिन्न थानो में भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के बोर्ड लगा सके और आमजन को पता चल सके की झूठी एफआईआर पर क्या कार्यवाही की जा सकती है इस पर सख्त कार्यवाही से आधी समस्या का समाधान देश मे हो जाएगा!

संक्षिप्त समाचार

दोस्त की शादी में गए युवक का हुआ पकड़ौवा विवाह, बाद में पता चला पत्नी थी शादीशुदा

पटना। बिहार राज्य महिला आयोग में एक मामला सामने आया है, जिसमें पति ने अपनी ही पत्नी के ऊपर दो बच्चों को मारने का आरोप लगाया है। पति ने बताया कि उसकी शादी पकड़ौवा विवाह था, लेकिन फिर भी उसने इस शादी को निभाते हुए अपनी पत्नी को अपने घर लाया। वहां उसे पता चला कि उसकी पत्नी पहले से ही शादीशुदा थी। दूसरी ओर पत्नी का कहना है कि उसके ससुरालवालों ने उसके ऊपर केरोसिन तेल डालकर जलाने की कोशिश की थी। अब दोनों महिला आयोग पहुंचे हैं। यह मामला पटना के सालीमपुर थाने का है। वहीं, आवेदिका नालंदा के इस्लामपुर थाने की है। दोनों की शादी 12 नवंबर 2024 को हुई थी। आवेदिका ने कहा, उपहार स्वरूप 4 लाख कैश और 2.5 लाख का सामान दिया गया था। शुरू के 7 महीने परिवार का व्यवहार ठीक , लेकिन उसके बाद पति सहित परिवार के अन्य लोग दहेज की मांग करने लगे। पति ने आवेदिका महिला पर किरासन तेल छिड़क कर, माचिस की तीली जलाकर जान से मारने की कोशिश की। किसी तरह महिला जान बचाकर वहां से भागी और अपने मायके नालंदा गई। उसे कुछ चोट भी आई थी, इसलिए वहां के सरकारी अस्पताल में उसका इलाज करवाया गया।

मिंटो हॉस्टल के 8 छात्रों को हिरासत में लिया, पटना विवि छात्रसंघ चुनाव के बीच वर्चस्व को लेकर बवाल

पटना। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया के बीच बुधवार देर रात विभिन्न छात्र संगठनों के बीच वर्चस्व को लेकर भिड़ंत हो गई। चुनावी माहौल के बीच कैंपस में तनाव की स्थिति हो गई, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। छात्र संघ चुनाव को लेकर अलग-अलग संगठनों के समर्थक आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लेने का प्रयास किया। सिटी एसपी पटना मध्य भानु प्रताप सिंह ने बताया कि पीरबहोर थाना समेत आसपास के कई थानों की पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया। देर रात विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने मिंटो छात्रावास से 8 छात्रों को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए छात्रों में से एक का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस सभी हिरासत में लिए गए छात्रों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। कैंपस में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। फिलहाल विश्वविद्यालय परिसर में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, हालांकि प्रशासन सतर्क है और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

मैट्रिक परीक्षा में सॉल्वर गैंग,10,000 में एक पेपर का सौदा, बांका से पकड़े गए 2 छात्र

पटना। बिहार मैट्रिक परीक्षा का आज तीसरा दिन है। दोनों पालियों में आज सेकेंड लैंग्वेज की परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिन परीक्षार्थियों की मातृभाषा हिंदी है, वे दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत, फारसी, अरबी या मगही में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। पहली पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है। इधर, मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन बांका में सॉल्वर गैंग के दो छात्र पकड़े गए। यहां 10 हजार रुपए में मैथ्स का पेपर पास कराने का सौदा हुआ था। आरएमके इंटर स्कूल परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी ओम कुमार की जगह बादल कुमार परीक्षा दे रहा था। वीक्षकों ने प्रवेश पत्र और पहचान पत्र की जांच के दौरान उसे पकड़ लिया। पूछताछ में बादल कुमार ने बताया कि ओम कुमार ने 10 हजार रुपए में उसे परीक्षा देने के लिए कहा था। इसमें से 7 हजार रुपए एडवांस दिए गए थे, जबकि बाकी रकम परीक्षा के बाद देने की बात हुई थी। वहीं, बाराहाट प्रखंड के मोहनपुर परीक्षा केंद्र पर भी एक और फर्जीवाड़ा सामने आया। यहां परीक्षार्थी बजरंगी कुमार की जगह प्राण कुमार परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में कुल 1699 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक हो रही है, जिसके लिए प्रवेश सुबह 9 बजे बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जा रही है।

वेस्टर्न रीति-रिवाज के बाद गांव में लिए सात फेरे, चेक गणराज्य देश के दूल्हे ने भारतीय दुल्हन से की शादी

पटना। बाढ़ अनुमंडल के रूपस गांव में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। चेक गणराज्य के दूल्हे ने भारतीय दुल्हन से शादी की। यह विवाह पहले चेक गणराज्य में वेस्टर्न रीति-रिवाज से संपन्न हुआ था, जिसके बाद नव दंपती भारतीय परंपरा से 7 फेरे लेने के लिए भारत लौटे। दुल्हन के पिता शशिकांत करीब 40 साल पहले चेक गणराज्य में बस गए थे। उनकी बेटी की परवरिश वहीं हुई और उसने चेक गणराज्य के ही एक युवक से शादी करने का फैसला किया। दुल्हन के परिजनों की इच्छा थी कि विवाह भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे से भी संपन्न हो। इसी चाहत को पूरा करने के लिए नव दंपती रूपस गांव पहुंचे। गांव में विधि-विधान के साथ मंडप सजाया गया और अग्नि के 7 फेरे लेकर विवाह की रस्में पूरी की गईं। विदेशी दूल्हे ने भी पूरे उत्साह के साथ भारतीय परंपराओं का पालन किया। शादी में दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए दूर-दूर से रिश्तेदार और ग्रामीण पहुंचे। लोगों ने इसे 2 संस्कृतियों के मिलन का प्रतीक बताया। सभी रस्में पूरी होने के बाद नव दंपती अब वापस चेक गणराज्य लौटने की तैयारी में हैं। दुल्हन के पिता शशिकांत ने बताया कि मैं 40 साल से चेक गणराज्य में रह रहा। 3 साल पहले अपने बेटे की शादी भी वहीं की एक लड़की से की थी, लेकिन बेटी की शादी गांव में ही करने की विशेष इच्छा थी, ताकि ग्रामीण आशीर्वाद दे सकें। उन्होंने जोर दिया कि जो लोग विदेश में रहते हैं, उन्हें अपने गांव और घर से रिश्ता बनाए रखना चाहिए। उनका परिवार होली और दशहरा जैसे त्योहारों पर गांव आता रहता है।

संदिग्ध परिस्थिति में अधेड़ का शव बरामद, परिजन ने 2 रिश्तेदार पर हत्या का लगाया आरोप

हाजीपुर। हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के कौनहारा घाट के पास डायल 112 पुलिस ने संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के पारु थाना अंतर्गत पारु गांव निवासी स्वर्गीय सूरज लाल चौधरी के बेटे पंकज चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जमीन विवाद के चलते रिश्तेदार धर्मेंद्र और विकास कुमार ने पंकज चौधरी की हत्या की है। जानकारी के अनुसार, कौनहारा घाट के पास एक अधेड़ का शव पड़ा होने की सूचना स्थानीय लोगों ने डायल 112 पुलिस को दी थी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और अधेड़ को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की बेटी रिया कुमारी ने बताया कि उनके पिता की बहन और उनके दामाद ने मिलकर उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। रिया के अनुसार, पुलिस उनके पिता को लगातार डरा-धमका रही थी और उन्हें 20 साल की सजा होने की बात कहकर परेशान किया जा रहा था। रिया कुमारी ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने मिलकर ही उनके पिता की हत्या की है।

पटना में रिटायर्ड आर्मी मैन की 3 गोली मारकर हत्या

एजेंसी, पटना

- गोपालपुर में जमीन पर बाउंड्री वॉल कराते वक्त किया शूट, जमीन विवाद का मामला

पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े एक सेवानिवृत्त आर्मी मैन की 3 गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मानपुर बैरिया इलाके में हुई, जहां जमीन नापते समय उन्हें गोली मारी गई है। उनको गंभीर हालत में उन्हें निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान अशोक नगर निवासी तेजनंदन राय (45) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, इस घटना के पीछे आपसी जमीन विवाद बताया जा रहा है। आरोपी की पहचान चोखा राय के नाती विकास कुमार के रूप में हुई है।

जमीन पर नापी करवाकर बाउंड्री वॉल बनवा रहे थेः सदर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी (2) रंजन कुमार ने बताया कि तेजनंदन राय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद ओडिशा में एक कंपनी में कार्यरत थे। उन्होंने साल 2005 में गोपालपुर बैरिया में चोखा राय से एक जमीन खरीदी थी। इसी जमीन पर चोखा राय का नाती विकास कुमार अपना दावा कर रहा था। गुरुवार को तेजनंदन राय उसी जमीन पर नापी करवाकर बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे। इसी दौरान विकास कुमार मौके पर पहुंचा और तेजनंदन राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। पुलिस ने घटनास्थल से गोली के तीन खोखे बरामद किए हैं।

पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही हैः पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी रंजन कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विकास ने तेजनंदन राय पर तीन गोलियां चलाई थीं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी विकास कुमार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सूचना पाकर मौके पर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार, सदर डीएसपी 2 रंजन कुमार दलबल के साथ पहुंचे हैं।

'विदेशी चीजों को अपना बताना चिंता का विषय'

एजेंसी, पटना

- गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद पर चिराग पासवान बोले, नीट छात्रा रेप-मौत केस पर कहा- परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए

एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, दूसरे देशों की चीजों को अपना बताकर पेश किया जाना गंभीर और चिंता का विषय है। इससे देश की अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित होती है'। 'देश में इस समय एआई समिट चल रहा है और उसके समापन के बाद सरकार इस मामले की पूरी समीक्षा करेगी। समिट खत्म होने के बाद तथ्यों के आधार पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, वह सरकार तय करेगी'।

देश की छवि पर पड़ सकता है असरः चिराग पासवान ने कहा कि भारत तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में यदि किसी संस्थान द्वारा विदेशी तकनीक या सामग्री को अपना बताकर प्रस्तुत किया जाता है, तो यह न केवल भ्रामक है बल्कि इससे देश की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि जांच में कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो संबंधित पक्षों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

जहानाबाद की रहने वाली नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में परिवार को कथित धमकी मिलने के मुद्दा पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परिवार की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पीड़ित परिवार को हर संभव सुरक्षा मिले और इस तरह की कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा न हो।

पटना में बना 'स्क्वॉयर स्ट्रीट', वेंडरों को मिलेगा स्थाई ठिकाना

एजेंसी, पटना

- सेल्फी पॉइंट, डिजाइनर लाइट के साथ डेवेलप हुआ ओपन एरिया, सेफ्टी के लिए है सीसीटीवी

पटना में लोगों को चिल करने के लिए एक नया एरिया डेवलप किया गया है। मंदिरी से सटे खटाल गली में विकसित नए क्षेत्र को 'स्क्वॉयर स्ट्रीट' नाम दिया गया है। यह पूरा इलाका स्क्वॉयर आकार में बनाया गया है, जो 2564 स्क्वॉयर मीटर में फैला हुआ है। यहां सीमेंट का पेवर ब्लॉक बिछाया गया है और बैठने के लिए बेंच लगाई गई है। इसके अलावा दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग और आधुनिक लाइटिंग से एरिया को सुंदर बनाया जा रहा है। पटना नगर निगम की ओसे से इसे एक तरह के वेडिंग जोन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जहां वेंडरों को व्यवस्थित तरीके से दुकान लगाने की सुविधा दी जाएगी। न्यू पुलिस लाइन, पटना म्युजियम और होटल ताज के आसपास की दुकानों को इस विकसित क्षेत्र में शिफ्ट करने की तैयारी है।तारामंडल से हटाए गए कई फूड वेंडर अभी पटना म्युजियम के पीछे की सड़क पर दुकानें लगा रहे हैं। इस इलाके में नई जगह विकसित होने से फूड वेंडरों को भी यह स्थायी जगह मिल सकेगी। इससे सड़कों पर जाम से निजात मिलेगी साथ ही स्थानीय स्तर पर कई लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

स्पीकर प्रेम कुमार समेत 42 विधायकों को नोटिस

एजेंसी, पटना

- चुनाव के दौरान नॉमिनेशन में गलत जानकारी देने का आरोप

पटना हाईकोर्ट ने पक्ष और विपक्ष के 42 विधायकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। इन 42 विधायकों में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक चेतन आनंद और गोह से राजद विधायक अमरेंद्र प्रसाद के नाम शामिल हैं। इन विधायकों पर चुनाव के दौरान वोट चोरी करने और नॉमिनेशन के दौरान चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने जीते हुए विधायकों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने चुनावी हलफनामे में कथित गलत जानकारी देने और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता के आरोपों को लेकर उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी संबंधित विधायकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार, संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिकाएं दायर की थीं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई और नामांकन के समय दाखिल किए गए शपथपत्र में तथ्यों को छुपाया गया या गलत जानकारी दी गई। इन्हीं आरोपों के आधार पर अदालत में याचिकाएं दाखिल की गईं। जिसके बाद गुरुवार को इन याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भी संबंधित विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब अदालत में दाखिल किए जाने वाले जवाब, साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर मामले की आगे की सुनवाई होगी।

कोर्ट के नोटिस पर क्या बोले विधायकः हाईकोर्ट के नोटिस के बाद कई विधायक मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। अधिकांश विधायकों ने कहा कि वे अपना जवाब अदालत में ही देंगे।

जीवेश मिश्रा ने कहा, "हाईकोर्ट का जवाब हमलोग हाईकोर्ट में ही देंगे।" अभिषेक रंजन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अगर किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो कोर्ट जाना उसका अधिकार है। अब क्या निर्णय होगा, यह अदालत तय करेगी।" वहीं भाई वीरेंद्र ने कहा, "कोर्ट की शरण लेना सबका अधिकार है और निर्णय लेना कोर्ट का अधिकार है।" बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने कहा, "यह कानूनी मामला है। सभी लोग अपना-अपना जवाब अदालत में देंगे।" इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजू तिवारी ने कहा, "यह न्यायपालिका का मामला है। इस पर क्या बोला जा सकता है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर सार्वजनिक टिप्पणी करना उचित नहीं है।"

बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद कई उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंचेः 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए। चुनाव में NDA को बंपर जीत मिली। परिणाम आने के बाद कुछ हारने वाले उम्मीदवारों ने कथित अनियमितताओं को लेकर पटना हाईकोर्ट का रुख किया।

नीट छात्रा केसः सीबीआई खंगाल रही भाई का मोबाइल

एजेंसी, पटना/जहानाबाद

- दरोगा से भी पूछताछ, दुष्कर्म हुआ या सहमति से संबंध बने, इसकी भी एजेंसी कर रही जांच

NEET छात्रा रेप-मौत मामले में CBI की टीम ने जांच शुरू कर दी है। CBI की टीम SIT, थाने की SI, छात्रा के परिवार वालों से पूछताछ कर चुकी है। गुरुवार को CBI ने कदमकुआं थाना के निलंबित सब इंस्पेक्टर हेमंत झा को दफ्तर बुलाकर करीब 30 मिनट तक पूछताछ की। दरअसल, जब छात्रा प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट थी। 6 जनवरी को ही इन्हें हॉस्पिटल की तरफ से मामले की जानकारी दी गई थी। शुरुआत में इन्होंने लापरवाही बरती थी। जब बाद में मामला तूल पकड़ने लगा तब इन्होंने परिवार का फर्द बयान दर्ज किया था। जिसके बाद चित्रगुप्त नगर थाना में FIR दर्ज हुई थी। लापरवाही बरतने के कारण ही पटना के एसएसपी ने हेमंत झा को सस्पेंड कर दिया था।

भाई के मोबाइल को अहम सुराग मान रही CBIः छात्रा के भाई का मोबाइल पान की दुकान पर मिला था।यह अब जांच का अहम सुराग बन गया है। एक अज्ञात व्यक्ति ने दुकानदार को मोबाइल देकर कहा था कि कोई लेने आएगा। दस मिनट बाद स्कॉर्पियो से पांच लोग पहुंचे और मोबाइल ले गए। दुकानदार ने बताया कि वह व्यक्ति का नाम नहीं जानता, पर पहचान सकता है। इसी कड़ी को जोड़ते हुए सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। पान दुकानदार ने सीबीआई की टीम को बताया कि एक व्यक्ति ने मोबाइल देकर कहा, कोई लेने आएगा। मैं उसका नाम नहीं जानता, पर पहचान सकता हूं। दस मिनट बाद स्कॉर्पियो से पांच लोग पहुंचे। मोबाइल लेकर चले गए।

भाई के मोबाइल का CDR खंगाल रही CBIः छात्रा के भाई के मोबाइल का सीडीआर खंगाला जा रहा है। उसे भी पटना बुलाया जा सकता है। एसआईटी की रिपोर्ट और बयान सीबीआई को सौंपे गए हैं। 5 जनवरी को छात्रा अकेले जहानाबाद से पटना लौटी थी। वह ट्रेन से पटना जंक्शन पहुंची। करबिगहिया छोर से बाहर निकली। ई-रिक्शा से हॉस्टल के पास उतरी। वहां से पैदल हॉस्टल गई। सीबीआई टीम ने इसी क्रम में सीन रीक्रिएट किया।

धमकी भरे लेटर के बाद एफएसएल जांचः धमकी भरे दो लेटर मिलने के बाद बुधवार को बिहार पुलिस की FSL की टीम जहानाबाद में पीड़ित परिवार के घर पहुंची थी। करीब डेढ़ घंटे तक टीम वहां रही। इस दौरान कई पॉइंट्स पर जांच किए गए। कई जगहों से FSL की टीम ने सैंपल कलेक्ट किए। घर के दरवाजों और खिड़की तक के साइज नापे गए। दरअसल, सादे कागज पर लिख कर पीड़ित परिवार को दो बार धमकी भेजी गई। दोनों के बीच महज 48 घंटे का ही अंतर है।

धमकी देने वाले शख्स ने लेटर में लिखा पहले बेटी गई। नहीं मानोगे तो अब बेटा भी जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या धमकी भरे पत्र को किसी एक ही इंसान ने लिखा है? इसका जवाब जानने के लिए FSL की टीम दोनों कागजों के लिखावट की जांच कर रही है। दूसरी तरफ धमकी मिलने के बाद से पीड़ित परिवार की सुरक्षा जहानाबाद पुलिस की ओर से की जा रही है। वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, 'परिवार की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पीड़ित परिवार को हर संभव सुरक्षा मिले और इस तरह की कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा न हो।

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव, उम्मीदवार को हिरासत में लिया

एजेंसी, पटना

पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया बुधवार को समाप्त हो गई। आज नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होगी और शाम 5 बजे कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल पैनल के पांच पद के लिए कुल 51 और काउंसलर के 22 पदों के लिए कुल 54 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है। अध्यक्ष पद के लिए 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं, महासचिव के लिए 9, उपाध्यक्ष के लिए 9, संयुक्त सचिव के लिए 4 और कोषाध्यक्ष पद के लिए 9 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है।

सभी प्राप्त नॉमिनेशन पेपर की जांच 19 फरवरी को जांच समिति करेगी। इसके बाद स्वीकृत और अस्वीकृत अध्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार जांच परिणाम से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह 20 फरवरी को दोपहर 1 बजे तक उच्च अपीलीय प्राधिकार के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकता है। उम्मीदवार 21 फरवरी तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। अंतिम रूप से योग्य उम्मीदवारों की सूची 21 फरवरी को यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित की जाएगी। वहीं, दूसरी तरफ पटना विमेंस कॉलेज के बाहर छात्र को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ABVP से टिकट नहीं मिलने के कारण अंचल कुमार के समर्थकों ने अभविप के कार्यालय में हंगामा किया था। अंचल कुमार और उसके समर्थकों ने बोला हमने नामांकन भर दिया फिर पार्टी ने किसी और लड़की को टिकट क्यों दिया। जिसके बाद हमारे समर्थकों ने कार्यालय जाकर इसका विरोध किया।

सरकारी अस्पतालों में 8 हजार पार मरीजों का आंकड़ा

एजेंसी, पटना

मौसम में बदलाव होने लगा है। सुबह-रात ठंड और दोपहर में गर्माहट है। इस कारण सीजनल बीमारी बढ़ गई है। पटना के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। IGIMS, PMCH और AIIMS पटना जैसे बड़े अस्पतालों में भारी भीड़ देखी गई, जहां बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचे। आंकड़ों के अनुसार, बुधवार को IGIMS की ओपीडी में 4339 मरीज पहुंचे, जबकि PMCH की ओपीडी में 1930 और एम्स पटना में 2870 मरीजों ने इलाज कराया। ओपीडी खुलने के साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर डॉक्टरों के कक्षों तक लंबी कतारें लग गईं। मरीजों और उनके परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ा।

आईजीआईएमएस के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल ने बताया कि मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण सर्दी, बुखार, जुकाम, शरीर दर्द, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी बीमारियों के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। जहानाबाद के ग्रामीण क्षेत्र से आए 60 वर्षीय शिवनाथ यादव सुबह आईजीआईएमएस पहुंचे। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और टोकन की प्रक्रिया समझ नहीं आने के कारण काफी देर तक भटकते रहे। किसी तरह पर्ची बनवाने के बाद भी डेढ़ से 2 घंटे तक ओपीडी चैंबर के बाहर इंतजार करना पड़ा।

बिहार में 100 पिंक बसें महिलाओं के लिए चल रहीं

एजेंसी, पटना

- 7 महिला ड्राइवरों को मिला लाइसेंस-प्रमाण पत्र, होली से पहले 149 नई बसें खरीदेगी सरकार

परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान का समापन समारोह आज अधिवेशन भवन में आयोजित किया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और यात्री सुविधा को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। मंत्री ने बताया कि राज्य में अगले एक महीने तक विभिन्न जिलों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आगे कहा, राज्य में फिलहाल 100 पिंक बसें चलाई जा रही हैं, जिनमें महिला ड्राइवर और महिला कंडक्टर तैनात हैं। इनमें केवल महिलाएं ही सफर कर सकती हैं। महिला सशक्तिकरण के तहत आज 7 महिला ड्राइवरों को ड्राइविंग लाइसेंस और प्रमाणपत्र दिया गया है। आज से ही उन्हें बसों का परिचालन सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य को अभी लगभग 250 महिला ड्राइवरों की जरूरत है। औरंगाबाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है और महीने के अंत तक 21 नई महिला ड्राइवर उपलब्ध होंगी।

अवैध डीजे वाहनों पर सख्ती, होली से पहले नई बसेंः होली से पहले 149 नई बसें खरीदी जा रही हैं, जिनमें 75 एसी बसें शामिल हैं, ताकि त्योहार के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिल सके। मंत्री ने स्पष्ट किया कि अवैध रूप से डीजे गाड़ियां चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं होली को देखते हुए सरकार ने पहले से व्यवस्था शुरू कर दी है।

800 स्कूलों में चला अवेयरनेस अभियानः मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक 800 सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में रोड सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में बच्चों को ट्रैफिक नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व और सुरक्षित सड़क व्यवहार के बारे में विस्तार से बताया गया। सरकार का उद्देश्य है कि कम उम्र से ही बच्चों में सड़क सुरक्षा की समझ विकसित हो।

दुर्घटना पीड़ितों के लिए नई सहायता योजनाः मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। पहले एक्सप्रेस वे और हाईवे पर दुर्घटना होने पर ही सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन अब किसी भी सड़क पर दुर्घटना होने की स्थिति में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए डेढ़ लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। साथ ही, दुर्घटना में घायल व्यक्ति की जान बचाकर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य 'गुड सेमेरिटन' को बढ़ावा देना और समय पर इलाज सुनिश्चित करना है।

संक्षिप्त समाचार

चंडीगढ़ में पंजाब सचिवालय व सीएम कार्यलय को बम से उड़ाने की धमकी

लोकतंत्र की शान : चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय को गुरुवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद सचिवालय की इमारत को खाली करवा लिया गया। इससे पहले भी हरियाणा व पंजाब सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। गुरुवार को धमकी मिलने के बाद पंजाब के साथ साथ एहतियातन हरियाणा सचिवालय को भी अलर्ट पर रखा गया है। आज मिले धमकी भरे मेल में सचिवालय के साथ साथ मुख्यमंत्री कार्यलय में विस्फोट करने का दावा किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी और लोगों को सचिवालय से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। पुलिस बल, सीआरपीएफ, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमों ने सचिवालय की जांच की लेकिन कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

हिसार : लुवास के नॉन-टीचिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

लोकतंत्र की शान : हिसार। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास), के नॉन-टीचिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चंडीगढ़ में शिष्टाचार भेंट कर अपनी लंबित मांगों को उनके समक्ष विस्तार से रखा। इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर कर्मचारियों ने गुरुवार को सेवा सुरक्षा अधिनियम (जॉब सिक्योरिटी एक्ट) को विश्वविद्यालयों में लागू किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा उन्हें आश्वस्त किया कि संबंधित अधिकारी इस विषय पर कार्य कर रहे हैं और शीघ्र ही विश्वविद्यालयों के कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने की दिशा में सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा सेवा सुरक्षा अधिनियम को कैबिनेट एवं विधानसभा से पारित किया जा चुका है, किंतु अभी तक इसे राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू नहीं किया गया है। इस कारण कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारी लंबे समय से इस अधिनियम को विश्वविद्यालय में लागू करने की मांग कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी सेवा सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। इससे पहले इन कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा से मिलकर उनसे भी यही मांग दोहराई। उन्होंने मंत्री से मांग की कि वे इस विषय को प्राथमिकता के आधार पर उठाते हुए विश्वविद्यालय में सेवा सुरक्षा अधिनियम लागू करवाने तथा कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सहयोग प्रदान करें। विश्वविद्यालय के नॉन-टीचिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री एवं राज्य सरकार के प्रति आशा व्यक्त की है कि उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे उन्हें सेवा सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

राज्य में 841 नई उचित मूल्य दुकानों की प्रक्रिया जारी, 442 का चयन पूर्ण

लोकतंत्र की शान : जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार द्वारा अब तक 841 नई उचित मूल्य दुकानों के लिए विज्ञप्तियाँ जारी की गई हैं। इनमें से 442 दुकानों की चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, जबकि 399 दुकानों की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले में भी 15 नई उचित मूल्य दुकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है। मंत्री गोदारा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में 5000 खाद्य सुरक्षा उचित मूल्य दुकानों को खोलने की घोषणा की थी, लेकिन उनमें से केवल 531 दुकानें ही खोली जा सकीं। इनमें से 38 दुकानें चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित की गई थीं। वे प्रश्नकाल के दौरान विधायक चन्द्रभान सिंह चौहान द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। मंत्री ने बताया कि नियमानुसार न्यूनतम 500 राशन कार्ड और 2000 इकाई पर एक उचित मूल्य दुकान खोलने का प्रावधान है। आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जिला कलक्टरों को नियमों में शिथिलता प्रदान करने के अधिकार दिए हैं, ताकि आवश्यकता के अनुसार नई दुकानें खोली जा सकें। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्र के विधायक द्वारा मांग किए जाने पर राज्य सरकार तत्परता से नई उचित मूल्य दुकान खोलने की कार्रवाई करेगी। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से अब तक कच्ची बस्ती भीलों की झोपड़ी, वार्ड संख्या 34 के लिए ही प्रस्ताव मिला है। मंत्री ने विधायक के मूल प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि राज्य में वर्ष 2022-23 से अब तक कुल 973 उचित मूल्य की दुकानें खोली जा चुकी हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में विगत एक वर्ष में 15 नई राशन दुकानों को स्वीकृति प्रदान की गई है। 29 सितम्बर 2025 और 30 अक्टूबर 2025 को विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बेगूं में 5, निम्बाहेड़ा में 3, बड़ी सादड़ी में 2 और कपासन में 5 नई दुकानें खोली जाएंगी। बेगूं क्षेत्र की 5 दुकानों के लिए साक्षात्कार पूर्ण हो चुके हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। शेष क्षेत्रों में नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर दुकानों का आवंटन किया जाएगा।

लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में सुधार की बनेगी योजना

लोकतंत्र की शान : जयपुर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि अजमेर शहर में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह गंभीर है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। शून्य काल में विधायक लक्ष्मण राम द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए विषय पर जवाब देते हुए मंत्री रावत ने सदन को आश्वस्त किया कि लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र को किसी भी प्रकार से प्रभावित किए बिना नदी के बहाव को सुचारू बनाने के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि लूनी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है। नदी के प्रवाह क्षेत्र को चौड़ा और मजबूत बनाकर पानी की निकासी व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा।

कुसमी में हत्या प्रकरण का निरीक्षण करने पहुंचे एसपी

» न्यायालयीन प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के कुसमी विकासखंड में चर्चित पुजारी हत्या प्रकरण को लेकर पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने बुधवार की रात विस्तृत निरीक्षण कर जांच की दिशा और गति का जायजा लिया। जहां एसपी रात लगभग 10 बजे कुसमी पहुंचे और करीब 11 बजे तक थाने में रिकॉर्ड की विधिवत जांच के साथ-साथ घटनास्थल, आरोपी के घर तथा संबंधित मंदिर का भी निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने विवेचना से जुड़े दस्तावेजों, केस डायरी और साक्ष्यों की स्थिति का बारीकी से परीक्षण किया। जहां निरीक्षण के दौरान मृतक पुजारी के परिजन भी थाने पहुंचे और एसपी से सीधे संवाद कर अपनी बात रखी। परिजनों ने निष्पक्ष व त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा जताई, जिस पर एसपी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से काम कर रही है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जा रही हैं। जहा मौके पर मौजूद अन्य ग्रामीणों ने भी एसपी से बातचीत कर मामले की प्रगति को लेकर जिज्ञासा व्यक्त की। जहां एसपी संतोष कोरी ने बताया कि हत्या प्रकरण की जांच किस चरण में है, अब तक क्या प्रगति हुई है और आगे किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है इन सभी बिंदुओं के मूल्यांकन हेतु वे कुसमी पहुंचे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि मर्डर से संबंधित समस्त रिकॉर्ड व साक्ष्य न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत शीघ्र प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि विधिक कार्यवाही में किसी प्रकार की देरी न हो। निरीक्षण के दौरान एसपी ने संबंधित अधिकारियों को जांच में शुद्धता, पारदर्शिता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। वहीं इसके अतिरिक्त एसपी ने तहसील लाइन से जुड़ी हालिया घटना का भी निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी एकत्रित की और कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि पुजारी की हत्या कुछ दिन पहले हुई थी, जिसे लाला केवट द्वारा अंजाम दिया गया था।

कैथल : गन्ने की फसल से समृद्ध हुआ किसान, एमडी ने किया निरीक्षण

लोकतंत्र की शान

कैथल। चीनी मिल कैथल के प्रबंध निदेशक कृष्ण कुमार ने गांव हाबड़ी में प्रगतिशील किसान सरदार प्रीतजोत सिंह के गन्ना फार्म का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खेतों में उगाई जा रही विभिन्न किस्मों का अवलोकन किया और खेती की पद्धतियों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान प्रबंध निदेशक कृष्ण कुमार ने किसानों से गन्ने की खेती को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गन्ना एक नकदी फसल है, जिससे किसानों की आय में स्थायी वृद्धि संभव है। उन्होंने बताया कि जिला कैथल में कई किसान गन्ने की खेती कर आर्थिक रूप से मजबूत बने हैं। गांव हाबड़ी के किसान प्रीतजोत सिंह इसका जीवंत उदाहरण हैं, जिन्होंने आधुनिक तकनीक और उन्नत बीजों के माध्यम से बेहतर उत्पादन हासिल किया है। प्रगतिशील किसान प्रीतजोत सिंह ने बताया कि महंगाई के इस दौर में गन्ना फसल किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। उन्होंने अपने फार्म पर अगेती और पछेती किस्मों की नर्सरी तैयार की है। उनके पास मुख्य रूप से कोक-

16202 और कोह-176 किस्म का बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा उन्होंने को-17018, को-16030 और को-118 किस्मों की भी बीजाई की है। किसान प्रीतजोत ने कहा कि गन्ने की खेती से न केवल अच्छी आमदनी होती है, बल्कि भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहती है। उन्होंने अन्य किसानों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक क्षेत्र में गन्ने की बुवाई कर आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाएं, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।

लापता नाबालिग किशोरी को बिहार से ढूंढ लाई चुरहट पुलिस

लोकतंत्र की शान

परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

लापता नाबालिग किशोरी को सीधी लाने के उपरांत तमाम वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण की गईं। तत्पश्चात उसे सुरक्षित रूप से उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया। अपनी बेटी को सकुशल वापस पाकर परिजनों ने सीधी पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त किया है। इस पूरी कार्यवाही और किशोरी की सुरक्षित वापसी में उप निरीक्षक दीपक बघेल थाना प्रभारी चुरहट, उप निरीक्षक आशा सिलावट, सहायक उप निरीक्षक अमोल सिंह,महिला प्रधान आरक्षक सुमित्रा सिंह,आरक्षक विवेक द्विवेदी की सराहनीय भूमिका रही।

सीधी। पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं एसडीओपी चुरहट रवि प्रकाश कोल के सतत मार्गदर्शन में चुरहट पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक लापता नाबालिग किशोरी को बिहार राज्य से सकुशल ढूंढ निकालने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इस संबंध में चुरहट पुलिस से मिली जानकारी अनुसार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग किशोरी के अचानक लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल टीम गठित कर किशोरी की तलाश हेतु निर्देशित किया गया था। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर तंत्र की मदद से किशोरी का लोकेशन बिहार में ट्रैक किया। थाना प्रभारी चुरहट उप निरीक्षक दीपक बघेल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम तत्काल बिहार रवाना हुई और स्थानीय स्तर पर घेराबंदी कर किशोरी को सुरक्षित ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान किशोरी ने बताया कि वह माता-पिता की डांट से क्षुब्ध होकर घर से निकल गई थी और कमाने-खाने के उद्देश्य से बाहर चली गई थी।

निगम का अतिक्रमण अमला सक्रिय, बजरंग कॉलोनी में अवैध कॉलोनी की हटाई गई संरचना, अमित साहू के द्वारा की जा रही थी अवैध प्लाटिंग

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी। नगर निगम कटनी के अतिक्रमण विभाग द्वारा शहर की सुचारू आवागमन व्यवस्था हेतु अस्थाई अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही के साथ ही अवैध निर्माण एवं बिना सक्षम अनुमति निर्माण कार्यों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को उपनगरीय क्षेत्र के शिवाजी वार्ड स्थित बजरंग कॉलोनी क्षेत्र में बिना सक्षम अनुमति की जा रही अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण दल ने स्थल से निर्मित संरचनाओं को हटाने की कार्यवाही की। निगम के क्षेत्रीय उपयंत्री जेपी बघेल एवं अतिक्रमण प्रभारी मानेन्द्र सिंह ने बताया कि बजरंग कालोनी में अवैध प्लाटिंग की सूचना मिलने पर निगम की कॉलोनी सेल एवं अतिक्रमण टीम के संयुक्त निरीक्षण के दौरान किसी अमित साहू नामक व्यक्ति द्वारा बिना किसी विधिसम्मत स्वीकृतियाँ प्राप्त किये निर्धारित नियमों के विपरीत कालोनी का निर्माण कराया जाना पाया गया। जिस पर संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए बिना अनुमति निर्मित की गई संरचना लगभग 150 मीटर रोड को जेसीबी मशीन से अलग करने की कार्यवाही की गई। क्षेत्रीय उपयंत्री जेपी सिंह बघेल ने बताया कि उक्त स्थल पर पूर्व में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित को नोटिस जारी करते हुए निगम कार्यालय से सक्षम अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही नियमानुसार निर्माण कार्य करने हेतु निर्देशित करने के बाद भी संबंधित द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर विधि अनुरूप कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया कि शहर में अवैध कॉलोनियों एवं नियम विरुद्ध निर्माण कार्यों पर सख्ती जारी रहेगी। नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार के निर्माण अथवा भू-विकास कार्य से पूर्व आवश्यक अनुमतियाँ अवश्य प्राप्त करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उर्मिलेश्वर धाम सीधी में प्रगट हुए श्रीकृष्ण राधा युगल सरकार

» उर्मिलेश्वर धाम में श्रीकृष्ण रासलीला की मनमोहक प्रस्तुति
» दण्डी स्वामी निर्भयानंद सरस्वती के सानिध्य में हो रहा आयोजन

लोकतंत्र की शान

आज होगी संगीत की प्रस्तुति

उर्मिलेश्वर धाम तिलक नगर पडऱा सीधी में चल रहे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन में आज राष्ट्रीय लोक गायिका सुश्री मान्या पाण्डेय के द्वारा लोक गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ ही 23 फरवरी को प्रशिद्ध लोक गायक नारेन्द्र बहादुर सिंह के निर्देशन में फाग गीतों की प्रस्तुति होगी। इसके साथ ही लोक नृत्य, लोक वाद्य एवं जनजातीय गीतों की भी प्रस्तुति की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए समाजसेवी विनय कुमार सिंह परिहार ने बताया कि उर्मिलेश्वर धाम तिलक नगर में 17 फरवरी से 26 फरवरी तक धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन किया जा रहा है। जिसमें रासलीला, लोक संगीत के आयोजन के साथ 26 फरवरी को शिवलिंग की स्थापना एवं विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। उन्होने बताया कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव दण्डी स्वामी निर्भयानंद सरस्वती के सानिध्य में पहली बार शहर में धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन हो रहा है। विनय कुमार सिंह ने शहर एवं जिले के समस्त आम जनों से उक्त रासलीला में पहुंचने की अपील की है।

सीधी। शहर के समीप तिलक नगर पडऱा के उर्मिलेश्वर धाम में परम पूज्य दंण्डी स्वामी निर्भयानंद महराज के परम सानिध्य में श्रीकृष्ण लीला प्रचार मंडल श्रीधाम वृंदावन कालीदह के व्यास स्वामी बृजेश शर्मा की मंडली के द्वारा श्रीकृष्ण रासलीला की मनमोहक प्रस्तुति दी जा रही है। उर्मिलेश्वर धाम में 18 फरवरी से 26 फरवरी तक रासलीला का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान लोक संगीत एवं फाग गीतों की प्रस्तुति भी की जाएगी। उक्त रासलीला का शुभारंभ बुधवार को किया गया। जिसमें समाजसेवी विनय कुमार सिंह परिहार एवं साथियों के द्वारा भगवान श्रीराधा कृष्ण युगल सरकार की आरती कर वृंदावन से आए समस्त रासलीला के कलाकारों को सम्मानित किया गया। प्रथम दिवस पर निकुंज की श्रीराधा कृष्ण एवं उनकी अष्ट सखियों के द्वारा रासलीला का मंचन किया गया। तत्पश्चात कंस संवाद, देवकी वसुदेव विवाह एवं कृष्ण जन्म की लीला की प्रस्तुति श्रीराम कृष्ण लीला प्रचार मंडल श्रीधाम वृंदावन के द्वारा किया गया। जिसमें ठाकुर जी श्रीकृष्ण की भूमिका दीवेश शर्मा, श्रीजी की भूमिका नैतिक शर्मा, श्रीजी की अष्ट सखियों की भूमिका में करण शर्मा, गोविंद शर्मा, रवि शर्मा, राजू शर्मा, देव कुमार शर्मा, रामवीर शर्मा ने मनमोहक प्रस्तुति दी। इसके साथ ही कान्हा जी दिगंबर शर्मा, हरीष शर्मा, छोटू मिश्रा, ऋषि मिश्रा ने भी मनपसंद अभिनय किया। श्रीराम कृष्ण प्रचार मंडल श्रीधाम वृंदावन कालीदह के व्यास बृजेश शर्मा के निर्देशन व मार्गदर्शन में सभी कलाकारों में अपनी-अपनी उत्कृष्ट प्रस्तुतियां रासलीला के दौरान दी। उक्त रासलीला में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर बाल लीला, बृज लीला, द्वारिका लीला सहित अन्य लीलाओं का मंचन प्रति दिन शायं 7 बजे से उर्मिलेश्वर धाम तिलकनगर पडऱा में किया जाएगा।

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग : बीमा कंपनी को तकनीकी आधार पर क्लेम रिजेक्ट करना पड़ा महंगा

चुकाने होंगे 2.26 लाख रुपये, कंज्यूमर कोर्ट ने ग्राहक के हक में दिया फैसला

लोकतंत्र की शान

जोधपुर। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक मामले में बीमा कंपनी की सारी दलीलें खारिज कर उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाया है। आयोग के अध्यक्ष राजकुमार सुथार और सदस्य दिलशाद अली की बेंच ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा कि अगर पॉलिसी में ओन डैमेज कवर शामिल है और इंजन डैमेज को स्पष्ट रूप से बाहर नहीं किया गया, तो कंपनी क्लेम देने से मना नहीं कर सकती। आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को परिवादी को 2 लाख 26 हजार 80 रुपये हर्जाने सहित मानसिक पीड़ा और कानूनी व्यय के भुगतान के आदेश दिए हैं। दरअसल भोपालगढ़ के रहने वाले रूपाराम ने 2019 में महिंद्रा मार्जो कार खरीदी थी, जिसका बीमा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस से कराया गया। जुलाई 2021 में भारी बारिश के दौरान कार का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन बीमा कंपनी ने तकनीकी बहाने बनाकर क्लेम ठुकरा दिया। इस मामले में रूपाराम ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी के वकील ने जोर देकर कहा कि परिवादी की कार का इंजन पानी घुसने के कारण खराब हुआ था। कंपनी के अनुसार, वाहन की पॉलिसी सिर्फ ओन डैमेज के लिए थी, और इंजन सेफ्टी के लिए स्पेशल इंजन प्रोटेक्टर एड-ऑन नहीं लिया गया था।

मैला ढोना मंजूर किया..पर धर्म नहीं बदला : संत उमेश गिरी

लोकतंत्र की शान

जोधपुर। मध्यप्रदेश के राज्यसभा सांसद और प्रख्यात संत उमेश गिरी महाराज ने कहा सनातन की शक्ति को करंट की तरह छूकर महसूस करने की जरूरत है। वे गुरुवार को जोधपुर प्रवास पर थे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने सनातन धर्म की शक्ति, धर्मांतरण के बढ़ते खतरे और पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा कि आजकल धन, संपत्ति और जमीन का लोभ देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जो महज दबाव और लालच का विषय है। उन्होंने वाल्मीकि समाज का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे देश में वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुस्लिम शासन में पायखाने साफ करना और सिर पर मैला ढोना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। उन्होंने ही सनातन धर्म को बचाए रखा है। जो लोग लोभ-लालच में आकर धर्म बदल रहे हैं, वे कभी सनातन की शक्ति को समझ नहीं पाएंगे। सांसद ने कहा कि पाश्चात्य सभ्यता का आकर्षण क्षणिक है। उन्होंने एक अनूठा उदाहरण देते हुए कहा, जैसे हम अर्थी और करंट को छूकर देखते हैं, वैसे ही प्रत्येक भारतीय को सनातन की पावर को छूकर देखना चाहिए। जब आप इसमें प्रवेश करेंगे, तभी आपकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी। घर वापसी के सवाल पर संत ने कहा कि अगर कोई अपनी मर्जी से गया है और वापस आना चाहता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनका रिटर्न होना हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं है, क्योंकि हम अपनी जगह पर बहुत मजबूती से खड़े हैं। हमारी परंपरा तो दो रोटी में से एक गाय-कुत्ते को देने की है, हम स्वाभिमानी हैं। अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना पर उन्होंने कहा कि अब देश का हर गांव और शहर अयोध्या बन गया है। लोगों का मन राममय है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से जो मर्यादा का सूत्र दिया, रामजी ने उसे जीकर दिखाया। आज के दौर में युवाओं को उसी मर्यादित क्षेत्र में रहने की आवश्यकता है।

ऑनलाइन नामांतरण नाम का, बिना सुविधा शुल्क नहीं दौड़ती फाइल

» हल्का पटवारियों की मनमानी चरम पर
» तहसीलदारो की भूमिका संदिग्ध, भ्रष्टाचार चरम पर

लोकतंत्र की शान

सीधी। प्रदेश सरकार आम आदमी को सरकारी झंझटों से बचाने के लिए आवश्यक योजनाओं को ऑनलाइन सेवा से जोड़ दिया है, लेकिन इन सेवाओं को पूरी तरह सरकारी तंत्र से फ्री न करने के चलते आज भी आम आदमी को सरकारी सुविधाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है। सीधी जिले के सरकारी कार्यालयों में फैले भ्रष्टाचार के चलते आम आदमी को सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए मजबूरन दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। मजे कि बात यह है जिन सेवाओं को सरकार द्वारा ऑनलाइन कर दिया गया है वह भी सीधी जिले में महज दिखावा साबित हो रही है। कहने के लिए रजिस्ट्री के नामांतरण की सुविधा सरकार ने ऑनलाइन कर दी है लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ऑनलाइन के बाद भी हल्का पटवारियों द्वारा बिना सुविधा शुल्क वाले प्रकरणों को उलझाने के लिए जानबूझकर फसा दिया जाता है। जबकि इन सेवाओं में कागजों की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती है, वाबजूद इसके हल्का पटवारियों के इशारे पर तहसीलदारों द्वारा भी ऐसी फाइलों को नजर अंदाज कर दिया जाता है। सूत्र बताते हैं कि शहर के कुछ चिन्हित हल्का पटवारियों द्वारा बिना सुविधा शुल्क किसी भी फाइल को आगे नहीं बढ़ाते हैं, और जिनके द्वारा मुंहमांगी सुविधा शुल्क उपलब्ध करा दी जाती हैं उनके प्रकरणों को तत्काल निराकृत कर दिया जाता है।

डायवर्सन के लिए भी किसान लगा रहे चक्कर

कहने के लिए सरकार जमीन की खरीदी बिक्री करने वालों को झंझटों से मुक्त करने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी है, लेकिन सीधी जिले में यह सुविधा बिना शुल्क दिए आगे नहीं बढ़ती है। नाम न छापने की शर्त पर एक किसान ने बताया कि नामांतरण एवं डायवर्शन की सुविधा को लेकर सरकार भले ही ऑनलाइन कर दिया गया है लेकिन यहां कुछ भी ऑनलाइन सुविधा नहीं मिल रही है। आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार भी उसी फाइल को देखते हैं जिसमें हल्का पटवारी की सहमति रहती हैं, बिना हल्का पटवारी के इशारे किसी भी फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है।

दिखावा साबित हो रहा सरकार का कानून

सरकार राजस्व विभाग की कई योजनाओं को ऑनलाइन सुविधा से जोड़ दिया है लेकिन सीधी जिले में सरकार का यह कानून सिर्फ दिखावा साबित हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि ऑनलाइन दर्ज आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन उनके निराकरण को लेकर न तो तहसीलदारों द्वारा सक्रियता दिखाई जा रही है और न बढ़ती संख्या की कलेक्टर का ध्यान जा रहा है। मजे की बात यह है कि लगातार बैठकों में कलेक्टर द्वारा इनकी समीक्षा भी की जाती है और शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए जाते हैं लेकिन जिले पटवारी व तहसीलदार अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं।

संक्षिप्त समाचार

ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू गिरफ्तार, एपस्टीन मामले में नाम, 17 साल की लड़की से रेप का आरोप

लंदन। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें सार्वजनिक पद पर रहते हुए गलत बर्ताव के शक में पकड़ा गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने उन्हें गुरुवार सुबह करीब 8 बजे सैंड्रिंघम में उनके घर से हिरासत में लिया। बता दें कि एंड्रयू का आज ही जन्मदिन है। दरअसल, एपस्टीन मामले में पीड़िता रही वर्जीनिया ग्रिफ़े ने आरोप लगाया था कि 2001 में जब वह 17 साल की थी तब प्रिंस एंड्रयू ने उनका यौन शोषण किया था। हालांकि, एंड्रयू ने ग्रिफ़े के सभी आरोपों को खारिज किया था। ग्रिफ़े की अप्रैल 2025 में मौत हो गई थी। इसकी वजह आत्महत्या बताई गई थी। इंग्लैंड में सार्वजनिक पद पर रहने हुए कदाचार गंभीर अपराध माना जाता है। इस अपराध में यह साबित होना जरूरी है कि व्यक्ति को पता था कि वह गलत कर रहा है, फिर भी उसने ऐसा किया। इस अपराध में अधिकतम सजा उम्रकैद हो सकती है। इस मामले की सुनवाई सिर्फ गंभीर आपराधिक आरोप के तहत अदालत में की जा सकती है। माना जा रहा है कि यह मामला उस समय से जुड़ा है जब एंड्रयू ब्रिटेन के ट्रेड एनवॉय (व्यापार दूत) थे। वह 2001 में इस पद पर नियुक्त हुए थे, लेकिन 10 साल बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस समय उनका नाम अमेरिकी अपराधी जेफ्री एपस्टीन के साथ संबंधों को लेकर विवादों में आया था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी दस्तावेजों में बताया गया था कि पद पर रहते हुए एंड्रयू का एपस्टीन से संपर्क था।

गगनयान मिशन के ड्रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन टेस्ट सफल, उड़ान से ज्यादा लोड डालकर किया चेक

चंडीगढ़। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए ड्रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा हुआ। क्वालिफिकेशन लेवल टेस्ट में अधिकतम उड़ान भार से ज्यादा लोड डालकर पैराशूट की मजबूती और सुरक्षा मार्जिन की जांच की गई। इस टेस्ट के बाद पक्का हुआ कि भारत मजबूत और बड़ी क्षमता वाले रिबन पैराशूट को डिजाइन और बनाने में पूरी तरह सक्षम है। साथ ही पैराशूट असली मिशन जैसी परिस्थितियों में भी सुरक्षित और ठीक तरह से काम करेगा। गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने के लिए ड्रोग पैराशूट बहुत जरूरी है। जब कैप्सूल पृथ्वी के वातावरण में लौटता है, तो यही पैराशूट उसकी तेज गति को कम करने में मदद करता है। यह टेस्ट बुधवार (18 फरवरी) को चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (TBRL) की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड (RTRS) सुविधा में किया गया। यह डायनेमिक टेस्ट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) की स्पेशल हाई-स्पीड एयरोडायनेमिक और बैलिस्टिक मूल्यांकन सुविधा RTRS में पूरा हुआ। इसमें इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गनाइजेशन (ISRO) के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC), DRDO की एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ADRDE) और TBRL की टीमों ने भाग लिया।

बेंगलुरु में पैरालाइज्ड पति के सामने महिला का गला काटा, 65 लाख के गहने लूटे

बेंगलुरु। बेंगलुरु के नेलमंगला में 70 साल की एक महिला की घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई। वारदात के समय उनका पैरालाइज्ड पति बिस्तर पर उनके पास ही लेटा था। ऐसा लग रहा था कि पति को पत्नी की हत्या की भनक भी नहीं लगी है। आरोपी महिला की हत्या के बाद करीब 65 लाख रुपए के सोने के गहने लूटकर फरार हो गया। मृतका का नाम शोभा था। वह अपने पति रंगनाथ के साथ कोटे बेदी इलाके में रहती थीं। दंपती की कोई संतान नहीं थी। रंगनाथ पिछले 15 साल से पैरालाइज्ड और बिस्तर पर हैं। घटना का खुलासा तब हुआ जब रंगनाथ को फिजियोथेरेपी देने पहुंचे डॉक्टर ने शोभा का खून से लथपथ शव बिस्तर पर पड़ा देखा। हत्या के आरोप पुलिस ने 36 साल के शिवकुमार नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वह एक दुकान का मालिक है और कपल के घर के पास ही रहता है। पुलिस के अनुसार, CCTV में आरोपी शिवकुमार रात करीब 1:03 बजे घर में दाखिल हुआ और शोभा का गला रेत दिया। वारदात के समय उनका पति पास ही लेटा था। हालांकि, वे घटना से अनजान रहे। पुलिस जांच में सामने आया कि शोभा ज्वेलरी कारोबारी की बेटी थीं और घटना के समय उन्होंने काफी सोने के गहने पहन रखे थे। आरोपी ने हत्या के बाद घर में नकदी की तलाश की। नकदी नहीं मिलने पर उसने उनकी चेन, कंगन और अन्य गहने उतार लिए। शोभा ने करीब 450 ग्राम सोने के गहने पहले थे, जिनकी कीमत लगभग 65 लाख रुपए आंकी गई है। CCTV फुटेज में आरोपी को घटना के बाद मोटरसाइकिल से भागते देखा गया।

फ्लाइट में हंगामा किया तो 30 दिन का बैन लगेगा

नई दिल्ली। फ्लाइट में बदसलूकी करने वाले पैसेंजर्स को एयरलाइंस अब सीधे 30 दिन के लिए बैन कर सकेंगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने हंगामा करने वाले यात्रियों से निपटने के लिए कड़े नियमों का सुझाव दिया है। नए प्रस्ताव में DGCA सभी एयरलाइंस को पैसेंजर्स पर डायरेक्ट कार्रवाई करने की पॉवर दे रही है। मौजूदा नियमों के मुताबिक, फ्लाइट में हंगामा करने वाले पैसेंजर्स की शिकायत सामने आने पर पहले जांच कमेटी बनती थी। इस दौरान एयरलाइंस को यात्रियों पर 45 दिन तक बैन लगाने की परमीशन मिलती थी। लेकिन नए नियमों में जांच कमेटी की जरूरत नहीं है। DGCA ने अपने बदले हुए नियमों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। ड्राफ्ट में कहा कि नए नियमों का मकसद एयरक्राफ्ट, यात्रियों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही एयरक्राफ्ट में अच्छा ऑर्डर और डिसिप्लिन बनाए रखना है। एजेंसी ने आगे सुझाव दिया कि एयरलाइन ऐसा एक्शन कई नियमों के उल्लंघन के लिए ले सकती है। इसमें एयरक्राफ्ट में स्मोकिंग करना, डोमेस्टिक फ्लाइट में शराब पीना और इमरजेंसी एग्जिट का गलत इस्तेमाल या लाइफ जैकेट जैसे लाइफ-सेविंग इक्विपमेंट का बिना इजाजत इस्तेमाल करना शामिल है। दूसरे प्रस्तावों के साथ, रेगुलेटर ने बताया है कि एक एयरलाइन बिगड़ैल पैसेंजर से निपटने और DGCA को घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाएगी और उसे लागू करेगी, और उसे सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स के बीच सर्कुलेट करेगी। एयरलाइन की ओर से बनाई गई एक इंडिपेंडेंट कमेटी उड़ान पर बैन लगाने पर फैसला लेगी। इस कमेटी में दूसरी एयरलाइन का एक रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होगा। रेगुलेटर ने कहा कि अगर कोई यात्री एयरक्राफ्ट में किसी भी तरह का हंगामा करते हुए मिलता है तो एयरलाइन उस पर सीधे 30 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए फ्लाइंग बैन लगा सकती है। इसमें केस को इंडिपेंडेंट कमेटी को नहीं भेजा जाएगा।

निहंग से भिड़ी महंत, बोली- मैं खुलेआम नंगी हो जाऊंगी, फिर देखना, मैं बंदा हूं या औरत

जालंधर। फरीदकोट से शुरू पाखंडी भगाओ, पंजाब बचाओ मुहिम कंट्रोवर्सी में घिर गई है। फिरोजपुर के महंतों के डेरे की प्रमुख नवीत कौर के साथ मुहिम चला रहे मनप्रीत सिंह खालसा दमदमी टकसाल का टकराव सोशल मीडिया पर आ गया है। बीबी नवीत कौर छांगे वाली का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें वह बाबा से कह रही है कि अगर आपको हमारे महंत होने पर शक है तो मैं कपड़े उतार देती हूं। नवीत कौर ने कहा- बाबा जी, मैं सरेआम नंगी हो जाऊंगी, उस समय फिर एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि सिंहों ने एक बीबी को नंगा किया। आप किसी को नंगा करने पर तुल गए हो। पहले गौरी महंत को कहा कि कपड़े खोल कर हम तेरे साथ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आप धमकियां देकर कह रहे हैं कि तेरे कपड़े खोलेंगे, हम तुझे देखेंगे कि तू बंदा है या औरत। क्या तुम सबके कपड़े खोलोगे? विवाद बढ़ने पर मनप्रीत सिंह ने इसकी शिकायत फिरोजपुर SSP को की। इसके बाद पुलिस ने बीबी के खिलाफ फिरोजपुर थाने में FIR दर्ज कर ली है। ये विवाद 3 महीने पहले उस समय शुरू हुआ जब मनप्रीत सिंह खालसा ने पाखंडी भगाओ, पंजाब बचाओ मुहिम शुरू की। इस मुहिम के तहत मनप्रीत सिंह और सिख जत्थेबंदियों ने कई डेरे से पाखंड करने वालों से माफी मंगवाई। बाबा जी, मैं सरेआम नंगी हो जाऊंगी: मनप्रीत सिंह ने डेरे और वहां स्मोकिंग करने पर सवाल उठाया। यह भी कहा गया कि ये महंत नहीं है। इस पर बीबी नवीत कौर भड़क गईं। नवीत कौर ने कहा कि बाबा जी, मैं सरेआम नंगी हो जाऊंगी, उस समय फिर एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि सिंहों ने एक बीबी को नंगा किया।

गाजा में कंट्रोल बढ़ा रहा हमास

एजेंसी, गाजा

- प्रभाव वाले इलाकों में 90% मौजूदगी
- ट्रम्प के पीस बोर्ड की बैठक आज, इसके दस्तावेजों में गाजा का ही जिक्र नहीं

अक्टूबर में अमेरिका की पहल पर लागू हुए सीजफायर के बाद गाजा में हमास ने अंदरूनी मोर्चे पर अपनी पकड़ फिर मजबूत कर ली है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, गाजा के एक कार्यकर्ता मोहम्मद दियाब ने कहा, 'हमास ने उन क्षेत्रों के 90% से अधिक हिस्से पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है जहां वह मौजूद है।' दियाब ने कहा, 'पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सड़कों पर लौट आई हैं। वे अपराध रोकने और जिन लोगों को सहयोगी या विरोधी मानते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं।' इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का 'बोर्ड ऑफ पीस' गुरुवार को वॉशिंगटन में अपनी पहली बैठक करेगा। इसमें करीब 60 देशों को आमंत्रित किया गया है। बैठक में गाजा पट्टी के लिए ट्रम्प की शांति योजना पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। हालांकि, टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, पीस बोर्ड के शुरुआती दस्तावेज में गाजा का ही स्पष्ट जिक्र नहीं है। ट्रम्प ने कहा कि बोर्ड का मिशन गाजा से कहीं आगे, पूरी दुनिया में शांति लाना है। कई यूरोपीय देशों ने इसे ट्रम्प का पर्सनल प्रोजेक्ट बताया और इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है।

ट्रम्प के कंट्रोल में होगा पूरा पीस बोर्ड: चार्टर के अनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प को इनॉगुरल चेयरमैन (प्रथम अध्यक्ष) नामित किया गया है, और यह पद लाइफटाइम उनके द्वारा चुने गए उत्तराधिकारी तक रह सकता है। उनके पास वीटो पावर है। बोर्ड के अधिकांश फैसलों को चेयरमैन की मंजूरी चाहिए होती है, जिसका मतलब है कि ट्रम्प किसी भी निर्णय को रोक सकते हैं। बोर्ड के सदस्यों को जोड़ने, हटाने एजेंडा तय करने, सब्सिडियरी बॉडी बनाने, ग्रुप भंग करने पर ट्रम्प का पूरा कंट्रोल होगा। राष्ट्रपति पद खत्म होने के बाद भी वे चेयरमैन बने रह सकते हैं, क्योंकि यह पद उनकी राष्ट्रपति पद से स्वतंत्र है। केवल एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सर्वसम्मति से उन्हें हटाया जा सकता है (जो व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी ट्रम्प ही नियुक्त करेंगे)।

विश्व नेताओं को बुला रहे ट्रम्प, पाकिस्तान भी शामिल: ट्रम्प ने सोमवार को कहा था, 'हम सभी विश्व नेताओं को बुला रहे हैं।' हालांकि, अब तक यह साफ नहीं है कि कितने राष्ट्राध्यक्ष खुद शामिल होंगे। बैठक डोनाल्ड जे. ट्रम्प यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में होगी। इस जगह का नाम हाल ही में बदला गया था। जर्मन न्यूज DW के मुताबिक करीब 60 देशों को बोर्ड में शामिल होने का न्योता भेजा गया था, जिनमें से लगभग 27 देशों ने शामिल होने पर सहमति दी है। इनमें अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन जैसे नेता भी शामिल हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने निमंत्रण स्वीकार किया है, लेकिन वे खुद नहीं आ रहे, उनकी जगह विदेश मंत्री आएंगे। बोर्ड में शामिल आधे से ज्यादा देश, अमेरिका की उस सूची में हैं जिनके नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। इनमें बेलारूस भी शामिल है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बैठक में शामिल होंगे। वहीं, मिडिल ईस्ट और यूरोप के कई देश केवल निचले स्तर के अधिकारियों को भेज रहे हैं या ऑब्जर्वर के रूप में भाग लेंगे।

राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी, आरोपी कोटा से पकड़ाया

एजेंसी, नई दिल्ली

करणी सेना के एक कार्यकर्ता ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुरुवार को यह दावा किया। उन्होंने धमकी वाला वीडियो भी सोशल मीडिया X पर शेयर किया है। पवन खेड़ा ने लिखा कि पूरा RSS-भाजपा तंत्र एक 'गोडसे फैक्ट्री' है। तथाकथित करणी सेना द्वारा राहुल गांधी और '25 सांसदों' के खिलाफ दी गई धमकी कोई अलग-थलग पड़ी घटना नहीं है। यह एक सुनियोजित और कपटपूर्ण साजिश का हिस्सा है। उन्होंने X पर लिखा- कट्टरपंथ ऐसे ही काम करता है। वे पहले एक झूठ बनाते हैं, पॉलिटिकल अथॉरिटी उसे आगे बढ़ाती हैं और तब तक फैलाती हैं जब तक उनके फॉलोअर्स के मन में नफरत और हिंसा नहीं भर जाती। तब भी गोडसे बनाया गया था। आज फिर एक और गोडसे को तैयार किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद कोटा पुलिस ने आरोपी राज आमेरा को पकड़ लिया है। भास्कर रिपोर्टर ने राजा आमेरा से बात की। उसने कहा- मुझे वीडियो की जानकारी नहीं है। विपक्ष ने फेक आईडी बनाकर वीडियो बनाया है। मैं सनातन से जुड़ा हुआ हूं। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं।

क्या है वायरल वीडियो में: वीडियो में खुद को करणी सेना का बताते हुए शख्स ने संसद में ओम बिरला के चैंबर में हुई घटना का जिक्र किया। शख्स की पहचान राज आमेरा के रूप में हुई है। वह कोटा के उद्योग नगर का है। करणी सेना का संभागीय प्रवक्ता है। करीब 3 दिन पहले ही प्रवक्ता बनाया गया है। राज आमेरा ने कहा कि ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के 25 सांसदों ने जो बदतमीजी की है। वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सब के पीछे राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। मैं चेतावनी देता हूं अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो उन 25 सांसदो के घर में तोड़फोड़ करेंगे और राहुल गांधी सुन लें उनके घर में घुसकर गोली मारेंगे। इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। मेरी मांग है कि उन 25 सांसदों पर कार्रवाई हो। मोदी सरकार में मंत्री किरेन रिजिजू को जो बयान सामने आया, उसे सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं।

शिवाजी जयंती- पुणे के शिवनेरी किले में भगदड़, 3 घायल

रास्ता संकरा होने से भीड़ जमा, महिलाएं और बच्चे फंस गए थे

एजेंसी, मुंबई

पुणे के जुन्नर इलाके में बुधवार रात शिवनेरी किले पर भगदड़ मचने से 3 लोग घायल हो गए। ये सभी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर किला पहुंचे थे। लोग हाथी दरवाजा और गणेश दरवाजा से किले के अंदर जा रहे थे। रास्ता संकरा होने से भीड़ जमा हो गई। फिर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। पुणे रूरल के एसपी संदीप सिंह गिल ने बताया कि सुबह तकरीबन 3:30 बजे भीड़ अग्नि ज्योति लेकर तेजी से रेलिंग की तरफ से नीचे उतर रही थी। वहां पुलिस पहले से मौजूद थी लोगों को रोकने की कोशिश की गई लेकिन तब तक लोग एक दूसरे पर गिर गए इसमे 3 के पैर मै चोट आई है एक का पैर मुड़ गया है और 2 लोग मामूली जख्मी हैं। घायलों को जुन्नर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जहां उनका इलाज जारी है। शिवाजी जयंती पर हर साल शिवनेरी किले में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। शिवनेरी किला महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर शहर के पास स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला है। यह किला खासतौर पर इसलिए मशहूर है क्योंकि यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था। किले में शिवाई देवी का मंदिर भी है, जिनके नाम पर शिवाजी महाराज का नाम रखा गया था।

फ्री खाना मिलेगा तो लोग काम क्यों करेंगे, मुफ्त बिजली-पानी देने से काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फ्रीबीज कल्चर (मुफ्त की रेवड़ियां) पर कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इसमें कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल हालत की परवाह किए बिना सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव था। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि देश के ज्यादातर राज्य राजस्व घाटे में हैं और फिर भी वे विकास को नजरअंदाज करते हुए मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कंपनी ने 2024 के विद्युत संशोधन नियमों के नियम 23 को चुनौती दी है। इसमें उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो-महीने में लगभग 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देती है, बिना किसी शर्त के यानी उपभोक्ता चाहे कितना भी खर्च करे, पहली 100 यूनिट के लिए बिल नहीं देना होता। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि बिजली दरों की घोषणा के बाद तमिलनाडु की कंपनी ने अचानक मुफ्त बिजली देने का फैसला क्यों किया।

सरकारें रोजगार दें

मुफ्त राशन बांटने पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले बयान: यह पहली बार नहीं है, जब कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर सख्त टिप्पणी की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी 2025 को कहा था, 'लोग काम करना नहीं चाहते, क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं। बिना कुछ किए उन्हें पैसे दे रहे हैं।' कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि इन लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की बजाय क्या आप मुफ्त की योजनाएं लागू करके परजीवियों की जमात नहीं खड़ी कर रहे हैं? वहीं 9 दिसंबर 2024 को भी केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था- कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा। सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही? तब कोर्ट अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान केंद्र ने अदालत को बताया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है।

हरियाणा पुलिस-किसानों के बीच झड़प

एजेंसी, अंबाला

- अंबाला में किसानों के टैंट उखाड़े, कई हिरासत में लिए, नेशनल हाईवे जाम करने पहुंचे

अंबाला में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। निर्माणाधीन रिंग रोड से खेतों में जाने का रास्ता देने की मांग को लेकर किसान 10 दिन से धरने पर बैठे थे। गुरुवार को पुलिस ने उनके तंबू उखाड़ दिए। कई किसानों को हिरासत में ले लिया। गुस्से में किसान अंबाला-जगाधरी नेशनल हाईवे जाने करने पहुंच गए। फिलहाल हाईवे पर भी भारी पुलिस बल तैनात है। किसानों का कहना है कि NHAI से बात भी चल रही थी। हालांकि कोई समझौता नहीं हो सका। रिंग रोड बनने से उनके खेतों को जाने का रास्ता नहीं बचेगा। बरसाती पानी की निकासी में भी दिक्कत होगी। किसान एनएचएआई से कोई आश्वासन ने मिलने के बाद मशीनों की घेराबंदी करने लगे। इसके बाद स्थिति बिगड़ गई। इसके बाद पुलिस और किसानों में झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने किसानों को खदेड़ते हुए बसों में बैठाना शुरू कर दिया।

5 हाईवे को जोड़ने को बन रहा रिंग रोड: अंबाला में 5 नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए रिंग रोड बनाया जा रहा है। इसका आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। रिंग रोड बनने के बाद अंबाला से चंडीगढ़ हाईवे (NH-152), अंबाला से रुड़की हाईवे (NH-344), अंबाला-जगाधरी (NH-444A), दिल्ली-अमृतसर (NH-44) और अंबाला-हिसार हाईवे (NH-65) एक दूसरे से जुड़ जाएंगे।

रास्ते के लिए 10 दिन से धरना: गांव सपेड़ा व आसपास के ग्रामीण रिंग रोड से खेतों में जाने का रास्ता मांग रहे हैं। इसी को लेकर गांव सपेड़ा के पास 10 दिन पहले धरना शुरू हुआ। इस दौरान एनएचएआई अफसरों से बात भी हुई। हालांकि कोई हल नहीं निकला।

हल न होता देख किसानों ने मशीनें घेरी: कई दिनों से चल रहे धरने से कोई हल न होता देख गुरुवार को किसानों ने रिंग रोड निर्माण में लगी मशीनों का घेराव शुरू कर दिया। मामला बिगड़ता देख एनएचएआई ने अंबा, महेशनगर और साहा थानों से पुलिस बुला ली गई। इसके बाद पुलिस किसानों को खदेड़ना शुरू कर दिया। कुछ किसानों को बस में बैठा लिया। जिससे मामला और बिगड़ गया। इसके बाद किसान नेशनल हाईवे की ओर कूच करने लगे।

NHAI ने काम शुरू करवाया: किसानों का धरना उखाड़ने के बाद NHAI ने यहां तेजी से काम शुरू करवा दिया। जनवरी के दूसरे सप्ताह में किसानों ने रिंग रोड का काम रुकवा दिया था। अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे थे कि धरना खत्म हो। रिंग रोड को समय पर पूरा करने का दबाव है। जैसे ही पुलिस ने किसानों के तंबू उखाड़े। किसानों ने सोशल मीडिया पर अपील कर और किसानों को जुटने का आह्वान किया। शाम 4 बजे काफी संख्या में किसान अंबाला-जगाधरी नेशनल हाईवे पर पहुंच गए। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने भी मंगलवार को महापंचायत की घोषणा की थी। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी से खुद सोशल मीडिया पर लोगों से अधिक से अधिक संख्या में पंचायत में पहुंचने की अपील की।

पंजाब सीएम ऑफिस-चंडीगढ़ कोर्ट उड़ाने की धमकी

एजेंसी, चंडीगढ़

चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय और चंडीगढ़ कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। एहतियातन हरियाणा सचिवालय को भी अलर्ट पर रखा गया है। जानकारी के मुताबिक, धमकी भरा ईमेल संबंधित विभाग को मिला था, जिसमें CM ऑफिस में विस्फोट करने की बात कही गई है। इस ईमेल का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। हालांकि, इसकी पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी ने पुष्टि नहीं की है। दैनिक भास्कर भी इस ईमेल की पुष्टि नहीं करता। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी और लोगों को सचिवालय से सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। पुलिस बल, CRPF, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉयड की टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरे इलाके की बारीकी से तलाशी ली। जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बता दें कि मंगलवार को भी मोहाली के अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसमें CM मान एडमिट थे। हालांकि, यह धमकी भी झूठी निकली थी। सामने आए ईमेल के स्क्रीनशॉट में दिख रहा है कि यह सचिवालय को आज सुबह 9 बजकर 46 मिनट पर मिला। इसमें लिखा है कि मान (CM भगवंत मान) का दफ्तर, सेक्रेटेरिएट और चंडीगढ़ कोर्ट में दोपहर 2.11 बजे धमाका होगा। इसके बाद लिखा है - पंजाब अब खालिस्तान बनकर रहेगा।

पाकिस्तान- सीएम मरियम के लिए लग्जरी जेट खरीदने का आरोप

एजेंसी, इस्लामाबाद

पाकिस्तान में पंजाब सरकार पर मुख्यमंत्री मरियम नवाज के लिए लग्जरी जेट खरीदने का आरोप लगा है। ट्रिब्यून एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गल्फस्ट्रीम G500 मॉडल के इस विमान की कीमत करीब 10 अरब पाकिस्तानी रुपए है। विमान की खरीद को लेकर सोशल मीडिया में विवाद तेज हो गया है। दावा किया जा रहा है कि यह जेट मुख्यमंत्री मरियम नवाज के उपयोग के लिए खरीदा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह विमान फिलहाल अमेरिका में रजिस्टर्ड है और अभी पाकिस्तान में इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर N144S बताया जा रहा है। पंजाब की सूचना मंत्री अजमा बोखारी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि यह जेट मुख्यमंत्री के लिए नहीं, बल्कि एयर पंजाब के लिए तैयार की जा रही फ्लीट का हिस्सा है।

गल्फस्ट्रीम G500 को दुनिया के सबसे लग्जरी बिजनेस जेट्स में गिना जाता है।

इसकी केबिन डिजाइन और सुविधाएं इसे आसमान में चलता फाइव-स्टार सुइट बनाती हैं। विमान में आमतौर पर 10 से 19 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होती है, जिसे जरूरत के मुताबिक तीन अलग-अलग रहने के हिस्सों में बांटा जा सकता है। सीटें पूरी तरह फ्लैट बेड में बदल जाती हैं। बीच में कॉन्फ्रेंस टेबल लगाई जा सकती है, जहां मीटिंग की जा सके। लंबी उड़ान के दौरान आराम के लिए अलग विश्राम क्षेत्र भी बनाया जा सकता है। G500 का केबिन इंडस्ट्री में सबसे शांत केबिन में गिना जाता है।

हिमाचल में टूरिस्ट वाहनों की एंट्री-फीस ढाई गुना तक बढ़ी

एजेंसी, शिमला

- कार, जीप पर 70 की जगह 170 रुपये लगेंगे, 1 अप्रैल से नई दरें लागू

हिमाचल प्रदेश की सैर महंगी होने वाली है। प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की एंट्री फीस 30 रुपए से लेकर 230 रुपए प्रति वाहन बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने नई दरें अधिसूचित कर दी है, जो कि एक अप्रैल 2026 से लागू होनी है। हिमाचल प्रदेश टोल्स एक्ट, 1975 के तहत अधिसूचित की गई नई दरों का असर न केवल बाहरी राज्यों के टूरिस्ट पर पड़ेगा, बल्कि सामान की ढुलाई की दरों में भी इजाफा होगा। सरकार ने प्राइवेट कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों पर लगने वाली एंट्री फीस 70 रुपए से बढ़ाकर सीधे 170 रुपए कर दी है। यानी 100 रुपए का इजाफा किया गया।

12 प्लस 1 सीटर वाहन की फीस 130 रुपए: इसी तरह, 12 प्लस 1 सीटर पैसेंजर वाहनों का शुल्क 110 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए किया गया है। मिनी बस (32 सीटर) का शुल्क 180 रुपए से बढ़ाकर 320 रुपए, जबकि कमर्शियल बसों के लिए शुल्क 320 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है।

निर्माण कार्य की मशीन की एंट्री फीस 800रु: निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली मशीनरी पर लगने वाला शुल्क 570 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए, बड़े मालवाहक वाहनों का शुल्क 720 रुपए से बढ़ाकर 900 रुपए, ट्रैक्टर के प्रवेश शुल्क में भी बढ़ोतरी करते हुए इसे 70 रुपए से 100 रुपए कर दिया गया है, जबकि डबल एक्सल बस-ट्रक की 570 रुपए (कोई बदलाव नहीं) फीस रखी गई है।

ऑनलाइन नीलामी और फास्टैग व्यवस्था: हिमाचल सरकार नई टोल बैरियर नीति के तहत एंट्री फीस की वसूली बैरियरों पर ही की जाएगी। इसके लिए फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा है। बैरियरों की नीलामी अब ऑनलाइन माध्यम से होगी। जिला स्तर पर डीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी, जो संचालन और निगरानी करेगी। ठेकेदारों को 15 दिन के भीतर फास्टैग सहित जरूरी व्यवस्थाएं लागू करनी होंगी। सरकार का दावा है कि इससे जाम कम होगा और आवाजाही सुगम बनेगी।

पर्यटन पर पड़ेगा असर?: एंट्री फीस की बढ़ौतरी की बढ़ौतरी ने टूरिस्ट के साथ साथ पर्यटन कारोबारियों की चिंताएं बढ़ा दी है। शिमला के होटेलियर अश्वनी सूद ने बताया कि एंट्री फीस की बढ़ौतरी का पर्यटन पर असर पड़ेगा। उन्होंने एंट्री फीस बढ़ौतरी को वापस लेने की मांग की है। टैक्सी ऑपरेटरों और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि बढ़े हुए शुल्क का सीधा असर पर्यटकों पर पड़ेगा। बता दें कि हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान इत्यादि प्रदेशों से हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट घूमने आता है।

रेवड़ी संस्कृति बनाम कल्याणकारी राज्य - सुप्रीम कोर्ट की फिर सख़्त टिप्पणी- मुफ़्तखोरी, खैरात की संस्कृतिः -लोकतंत्र,अर्थव्यवस्था और संवैधानिक दायित्व के बीच संतुलन की अनिवार्यता

लोकतंत्र की शान

» रेवड़ी संस्कृति पर नियंत्रण केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, नागरिक जागरूकता और आर्थिक विवेक का सम्मिलित परिणाम होगा

» क्या संसाधनों का उपयोग उत्पादक परिसंपत्तियों में हो रहा है या उपभोग में?क्या करदाताओं के धन का उपयोग पारदर्शी और न्यायसंगत है? क्या भविष्य की पीढ़ियों पर ऋण का बोझ अनावश्यक रूप से डाला जा रहा है? -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ 142.6 करोड़ से अधिक नागरिकों की आकांक्षाएँ, आवश्यकताएँ और अधिकार एक जटिल राजनीतिक-आर्थिक ढांचे के माध्यम से संचालित होते हैं। लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है,परंतु जब यह प्रतिस्पर्धा विकासात्मक दृष्टि के स्थान पर अल्पकालिक लोक लुभावन वादों में बदल जाती है,तब उसके दूरगामी परिणाम राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना दोनों पर पड़ते हैं। हाल के वर्षों में चुनावी मौसम में मुफ्त सुविधाओं, बिजली,पानी,नकद हस्तांतरण, लैपटॉप साइकिल इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं,उपभोक्ता वस्तुएँ, परिवहन,उपकरण विद्यार्थी अनेक मुफ्त बांटने कीघोषणाओं ने रेवड़ी संस्कृति को एक प्रमुख राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। यह बहस केवल राजनीतिक विमर्श नहीं है,बल्कि संविधान,वित्तीय अनुशासन, करदाताओं के अधिकार और भावी पीढ़ियों की आर्थिकसुरक्षा से जुड़ा प्रश्न बन चुकी है।अभी फिर से एक बार गुरुवार दिनांक 19 फरवरी 2026 को भारत क़ी सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ,सीजेआई सूर्यकांत,जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली ने तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम के मामले की सुनवाई के दौरान मुफ्त बिजली की संस्कृति पर कठोर टिप्पणी की।अदालत ने स्पष्ट कहा कि उपभोक्ता क़ि वित्तीय स्थिति का परीक्षण किए बिना सार्वभौमिक रूप से मुफ्त बिजली देना राज्य के आर्थिक विकास को बाधित कर सकता है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि न्यायालय की यह टिप्पणी केवल एक राज्य तक सीमित नहीं थी;यह समग्र नीति-दृष्टि पर प्रश्नचिह्न था।अदालत ने इंगित किया कि जब राज्य पहले से ऋणग्रस्त हों और विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन सीमित हों,तब खैरात आधारित राजनीति वित्तीय अनुशासन को कमजोर करती है और दीर्घकालीन बुनियादी निवेशों, जैसे आधारभूत संरचना,स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करती है। 21 जनवरी 2026 को भी शीर्ष न्यायालय ने इस विषय को अत्यंत महत्वपूर्ण करार देते हुए लंबित याचिकाओं की शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता पर बल दिया था। याचिकाकर्ता ने देश पर बढ़ते सार्वजनिक ऋण लगभग 250 लाख करोड़ रूपए की ओर ध्यान आकृष्ट किया। न्यायालय ने स्वीकार किया कि नीति-निर्णय का क्षेत्र कार्यपालिका का है,परंतु यह भी पूछा कि क्या राज्य के राजस्व का एक सुनिश्चित हिस्सा केवल विकास कार्यों के लिए सुरक्षित नहीं होना चाहिए? यह प्रश्न संघीय ढांचे के भीतर वित्तीय उत्तरदायित्व और जनहित के संतुलन का मूल प्रश्न है।

साथियों बात अगर हम न्यायालय की टिप्पणियों को गहराई से समझने की करें तो उसका एक केंद्रीय बिंदु था कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी फ्रीबीज के बीच अंतर। संविधान के नीति निदेशक तत्व राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपते हैं। यदि राज्य निर्धन या वंचित वर्गों को मुफ्त शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधा देता है,तो वह संवैधानिक दायित्व का निर्वहन है। किंतु जब बिना लक्षित पहचान के, बिना वित्तीय क्षमता के आकलन के, व्यापक स्तरपर मुफ्त वस्तुओं का वितरण केवल चुनावी लाभ हेतु किया जाए,तब वह नीति-आधारित कल्याण नहीं बल्कि अल्पकालिक राजनीतिक निवेश प्रतीत होता है।अदालत ने रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने कीआवश्यकता रेखांकित करते हुए कहा कि उत्पादक क्षमता को बढ़ाने वाली नीतियाँ ही दीर्घकालीन समाधान हैं। साथियों बात अगर हम आर्थिक दृष्टि इस मुद्दे को समझने की करें तो रेवड़ी संस्कृति का सबसे बड़ा प्रभाव राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण पर पड़ता है। राज्यों का बड़ा हिस्सा पहले ही वेतन,पेंशन और ब्याज भुगतान में खर्च हो जाता है।यदि अतिरिक्त संसाधन मुफ्त योजनाओं में लगाए जाते हैं, तो पूंजीगत व्यय सड़क,जल प्रबंधन,ऊर्जा ढांचा,औद्योगिक क्लस्टर के लिए संसाधन घटते हैं। इससे रोजगार सृजन की गति धीमी होती है और कराधान का आधार भी सीमित रहता है। एक दुष्चक्र बनता हैः कम निवेश कम उत्पादन, कम राजस्व,अधिक उधारी और अधिक लोकलुभावन घोषणाएँ। न्यायालय द्वारा परजीवी मानसिकता की आशंका इसी आर्थिक तर्क से जुड़ी है,यदि नागरिकों को उत्पादक अवसरों के स्थान पर अनुदान आधारित निर्भरता की ओर प्रेरित किया जाए, तो श्रम भागीदारी और नवाचार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। साथियों बात अगर हम लोकतांत्रिक विमर्श का एक अन्य पहलू चुनावी समानता और निष्पक्षता है इसकोसमझने की करें तो,यदि राजनीतिक दल करदाताओं के धन से भविष्य में दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं का वादा कर मतदाताओं को प्रभावित करते हैं,तो क्या यह चुनावी प्रतिस्पर्धा की नैतिक सीमा का उल्लंघन है? चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों में घोषणापत्रों की पारदर्शिता की बात कही गई है, परंतु उनके वित्तीय स्रोत और व्यावहारिकता का स्वतंत्र मूल्यांकन अनिवार्य नहीं है। इस संदर्भ में न्यायालय का यह संकेत महत्वपूर्ण है कि गंभीर मामलों को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, ताकि व्यापक संवैधानिक प्रश्नों पर स्पष्टता आए।रेवड़ी संस्कृति का सामाजिक आयाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है।भारत में ऐतिहासिक रूप से सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ रही हैं। कल्याणकारी योजनाएँ सामाजिक न्याय का उपकरण रही हैं,मिड-डे मील,सार्वजनिक वितरण प्रणाली, छात्रवृत्ति, मनरेगा जैसे कार्यक्रमों ने गरीबी उन्मूलन में योगदान दिया है। इसलिए किसी भी बहस में यह सावधानी आवश्यक है कि वास्तविक कल्याणकारी योजनाओं को फ्रीबीज कहकर खारिज न किया जाए।न्यायालय ने भी शिक्षा और स्वास्थ्य को संवैधानिक दायित्व के रूप में स्पष्ट किया।इसलिए मूल प्रश्न यह है कि लक्षित, आवश्यकता -आधारित, पारदर्शी और वित्तीय रूप से टिकाऊ योजनाओं और सार्वभौमिक,अस्थायी, चुनावी लाभ वाली योजनाओं के बीच रेखा कैसे खींची जाए।यदि इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने हेतु कठोर कानून बनाने की बात हो, तो उसका उद्देश्य प्रतिबंध मात्र नहीं बल्कि संतुलन स्थापित करना होना चाहिए। संभावित कानून का नाम हो सकता है,राष्ट्रीय राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं चुनावी लोकलुभावन व्यय विनियमन अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक चुनावी घोषणा के लिए अनिवार्य वित्तीय स्रोत-प्रमाणन,स्वतंत्र आर्थिक मूल्यांकन और दीर्घकालिक प्रभाव विश्लेषण की व्यवस्था की जा सकती है। एक स्वतंत्र चुनावी व्यय एवं लोकलुभावन नीति मूल्यांकन आयोग गठित किया जा सकता है, जो घोषणापत्रों की व्यवहार्यता पर सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करे। साथ ही, राज्य के बजट का एक न्यूनतम प्रतिशत पूंजीगत व्यय हेतु सुरक्षित रखने का संवैधानिक प्रावधान भी किया जा सकता है।साथ ही यह भी आवश्यक है कि पारदर्शिता को बढ़ाया जाए। यदि कोई राज्य मुफ्त बिजली देना चाहता है,तो उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसका वित्तीय स्रोत क्या है, कितनी अवधि तक योजना चलेगी,और उसका ऋण- जीडीपी अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा।संसद और विधान सभाओं में पूर्व- अनुमोदन और सार्वजनिक विमर्श की बाध्यता लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करेगी।न्यायालय का हस्तक्षेप नीति-निर्माण में प्रत्यक्ष दखल नहीं बल्कि संवैधानिक मर्यादा की तत्परता से याद दिलाना है। साथियों बात अगर हम इस मुद्दे पर एक सख्त कानून बनाए जाने की करें तो मेरा सुझाव है क़ि भारत में चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा रेवड़ियां (मुफ़्त उपहार, नकद लाभ, वादों के रूप में प्रत्यक्ष प्रलोभन) बाँटने का मुद्दा अक्सर लोकतांत्रिक नैतिकता और वित्तीय अनुशासन से जोड़ा जाता है। इस संदर्भ में यदि अत्यंत सख्त और निवारक कानून की परिकल्पना की जाए, तो वें प्रभावशाली,स्पष्ट और दंडात्मक भावना वाले होने चाहिए। मेरे विचार से संभावित कठोर विधेयक/अधिनियम नाम सुझाए जा रहे हैं(1)लोकतांत्रिक शुचिता एवं चुनावी प्रलोभन निषेध अधिनियम, 2026 (2) चुनावी रेवड़ी उन्मूलन एवं कठोर दंड अधिनियम, 2026 (3) राजकोषीय अनुशासन एवं लोकलुभावन वादा नियंत्रण अधिनियम, 2026(4) चुनाव प्रलोभन अपराध नियंत्रण एवं दंड संहिता अधिनियम, 2026 (5) राजनीतिक वित्तीय पारदर्शिता एवं मुफ्त वितरण प्रतिबंध अधिनियम, 2026 (6) जनमत प्रलोभन निषेध एवं लोकधन संरक्षण अधिनियम, 2026(7) चुनावी लोकलुभावन घोषणापत्र विनियमन एवं दंड अधिनियम, 2026(8) लोकतंत्र संरक्षण (अवैध चुनावी लाभ वितरण निषेध) अधिनियम, 2026 (9) राजनीतिक जवाबदेही एवं अनुदान दुरुपयोग निवारण अधिनियम, 2026 (10) चुनावी भ्रष्ट आचरण (मुफ्त वस्तु/नकद प्रलोभन) पूर्ण प्रतिबंध अधिनियम, 2026 साथियों बात अगर हम इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने की करें तो भी यह प्रश्न नया नहीं है। कई लोकतांत्रिक देशों में चुनावी वादों की सीमा तय करने के लिए राजकोषीय नियम बनाए गए हैं। यूरोपीय संघ में सदस्य देशों पर घाटे और ऋण की सीमा संबंधी मानक लागू हैं। लैटिन अमेरिकी देशों ने अतीत में लोकलुभावन व्यय के कारण आर्थिक संकट झेले हैं, जहाँ अत्यधिक सब्सिडी और मुफ्त वितरण ने मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन को जन्म दिया। भारत जैसे उभरते अर्थतंत्र के लिए यह चेतावनी है कि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ दीर्घकालिक आर्थिक अस्थिरता का कारण न बन जाए। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि प्रश्न यह नहीं कि कल्याणकारी राज्य होना चाहिए या नहीं, भारत का संविधान स्वयं एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करता है। प्रश्न यह है कि क्या कल्याण दीर्घकालिक सशक्तिकरण की दिशा में है या अल्पकालिक निर्भरता की ओर? क्या संसाधनों का उपयोग उत्पादक परिसंपत्तियों में हो रहा है या उपभोग में?क्या करदाताओं के धन का उपयोग पारदर्शी और न्यायसंगत है? और क्या भविष्य की पीढ़ियों पर ऋण का बोझ अनावश्यक रूप से डाला जा रहा है?न्यायपालिका की हालिया टिप्पणियाँ इस बहस को एक नई गंभीरता प्रदान करती हैं।यदि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मिलकर एक संतुलित ढांचा विकसित करें जहाँ सामाजिक न्याय,आर्थिक अनुशासन और लोकतांत्रिक नैतिकता का समन्वय हो तो भारत न केवल अपनी राजकोषीय स्थिरता को सुरक्षित रख सकेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक उत्तरदायी लोकतंत्र का उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा। रेवड़ी संस्कृति पर नियंत्रण केवल कानून का विषय नहीं,बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति,नागरिकजागरूकता और आर्थिक विवेक का सम्मिलित परिणाम होगा। यही संतुलन भारत को सशक्त, आत्मनिर्भर और दीर्घकालिक विकास की दिशा में अग्रसर कर सकता है।

-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9284141425

चीन की नई कूटनीति या पुरानी चाल? भारत के लिए भरोसा या भविष्य का धोखा

लेखक- कांतिलाल मांडोत

हाल के वर्षों में उपग्रह तस्वीरों और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह संकेत मिले हैं कि चीन अपने सामरिक ढांचे को तेजी से मजबूत कर रहा है। दक्षिण-पश्चिमी प्रांतों में पहाड़ों के भीतर बने बड़े-बड़े बंकर, भूमिगत सुरंगें और अत्याधुनिक सुविधाएं इस ओर इशारा करती हैं कि बीजिंग अपनी दीर्घकालिक रणनीति पर चुपचाप काम कर रहा है। ऐसे समय में जब वह भारत के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने और सहयोग बढ़ाने की बात करता है, यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या चीन वास्तव में भरोसेमंद साझेदार बनना चाहता है या यह उसकी रणनीतिक नीति का हिस्सा है। इतिहास गवाह है कि भारत और चीन के संबंधों में विश्वास की कमी की जड़ें गहरी हैं। वर्ष 1962 में चीन द्वारा भारत पर किया गया हमला दोनों देशों के रिश्तों में एक स्थायी अविश्वास की दीवार खड़ी कर गया। उसके बाद से सीमा विवाद, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव और समय-समय पर होने वाली झड़पों ने यह स्पष्ट किया कि संबंधों में गर्मजोशी और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर है। चीन ने कई बार शांति और सहयोग की बात की, लेकिन समानांतर रूप से अपनी सैन्य और सामरिक ताकत को भी बढ़ाया। चीन की विदेश नीति को समझने के लिए उसकी दीर्घकालिक रणनीतिक सोच को देखना जरूरी है। वह तात्कालिक भावनाओं के बजाय दशकों आगे की योजना बनाकर चलता है। उसकी प्राथमिकता अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और विस्तार है। चाहे वह दक्षिण चीन सागर हो, ताइवान का मुद्दा हो या हिमालयी सीमा हर जगह उसकी नीति शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में झुकाने की रही है। ऐसे में यदि वह भारत के साथ रिश्ते सुधारने की पहल करता है, तो यह केवल सद्भावना का परिणाम नहीं बल्कि एक सुविचारित रणनीति भी हो सकती है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में चीन कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक तनाव, तकनीकी प्रतिबंध और सामरिक प्रतिस्पर्धा ने उसे नए संतुलन की तलाश में डाल दिया है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक और सामरिक शक्ति है। एशिया में स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए भारत के साथ टकराव चीन के हित में नहीं है। इसलिए संभव है कि वह सीमित सहयोग और नियंत्रित प्रतिस्पर्धा की नीति अपनाए, ताकि वह एक साथ कई मोर्चों पर संघर्ष से बच सके। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि चीन की नीतियों में पारदर्शिता का अभाव रहा है। उसकी सैन्य तैयारियों और परमाणु ढांचे के विस्तार को लेकर अक्सर बाहरी दुनिया को सीमित जानकारी ही मिलती है। यदि उपग्रह तस्वीरों में दिखाई देने वाले निर्माण सचमुच सामरिक क्षमताओं के विस्तार का संकेत हैं, तो यह भारत सहित पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। एक ओर संवाद और व्यापार की बातें, दूसरी ओर पहाड़ों के भीतर बनते ठिकान यह दोहरी तस्वीर सहज भरोसा पैदा नहीं करती। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वह चीन के इरादों को कैसे परखे। केवल बयानों के आधार पर विश्वास करना रणनीतिक भूल हो सकती है। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए संवाद के द्वार खुले रखने होंगे। कूटनीति में संतुलन और सैन्य तैयारी में सतर्कता दोनों समान रूप से जरूरी हैं। चीन के साथ संबंधों को पूरी तरह टकराव की दिशा में ले जाना भी समझदारी नहीं होगी, क्योंकि दोनों देश एशिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और परस्पर निर्भरता भी बढ़ी है। चीन की नियति को समझने के लिए यह भी देखना होगा कि वह वैश्विक शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। उसकी बेल्ट एंड रोड पहल, तकनीकी निवेश और वैश्विक संस्थाओं में बढ़ती भूमिका इस दिशा का संकेत देती है। ऐसे में वह भारत को प्रतिस्पर्धी भी मानता है और संभावित साझेदार भी। यदि भारत उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए चुनौती बनता है, तो प्रतिस्पर्धा तीखी हो सकती है। लेकिन यदि भारत संतुलित और आत्मविश्वासी नीति अपनाता है, तो सहयोग के अवसर भी बन सकते हैं। भरोसे का निर्माण केवल शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से होता है।

वेस्टयूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग को धार देते आंदोलनकारी

अशोक मधुप

पश्चिमी उत्तर प्रदेश (वेस्ट यूपी) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित करने की मांग एक बहुत पुराना और लगातार जारी रहने वाला आंदोलन है। लगभग 70 साल पुरानी यह मांग केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की एक गहरी पुकार है। इस आंदोलन के कामयाब न होने की खास बात यह रही कि आंदोलनरत वकील आदोलन से जनता को नही जोड़ सके। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के वकीलों अपनी गलती समझ गए। उन्होंने रणनीति में बदलाव किया है। वह इससे पश्चिम उततर प्रदेश की जनता को जोड़ने में लग गए हैं। जनता को बैंच बनने के फायदें बता रहे हैं। अन्य जनप्रतिनिधियों का समर्थन ले रहे हैं। केंद्र सरकार और विधि मंत्रालय को उनसे समर्थन पत्र लिखवा रहे हैं। 1948 में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित की गई थी, लेकिन पश्चिमी यूपी को इससे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि लखनऊ भी इस क्षेत्र से काफी दूर था। वैसे 1955 की विधि आयोग की सिफारिशों ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। आयोग ने सिफारिश की थी कि उच्च न्यायालय की बेंच उन क्षेत्रों में स्थापित की जानी चाहिए, जहाँ से दूरी अधिक है। साल 1955 में तत्कालीन मुख्यमंत्री संपूर्णानंद ने मेरठ में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की सिफारिश की । वर्ष 1976 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने केंद्र को खंडपीठ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव भेजा । जनता पार्टी के शासन में राम नरेश यादव की सरकार ने भी इस मांग पर मुहर लगाई और पश्चमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव को कर उसे केंद्र सरकार को भेजा। बनारसीदास सरकार एवं बाद में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में भी एक प्रस्ताव पारित कर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को संस्तुति प्रदान की गईं । प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। 1970 और 1980 के दशक में, यह आंदोलन और भी जोर पकड़ने लगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों ने हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। किसान नेता चौधरी चरणसिंह, मुलायम सिंह यादव और अजित सिंह जैसे नेताओं ने भी इस मांग को अपना समर्थन दिया। इससे यह मांग राजनीतिक मुद्दा बन जरूर बन गई किंतु नेताओं की इच्छा शक्ति के अभाव में और इलाहाबाद के वकीलों के दबाव में कभी पूरी नही हुई। आज भी, पश्चिमी यूपी के कई संगठन और बार एसोसिएशन इस मुद्दे पर नियमित रूप से आंदोलन करते रहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों जैसे मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मथुरा से इलाहाबाद की दूरी 500 से 700 किलोमीटर है। इस लंबी दूरी के कारण मुवक्किलों और वकीलों को अत्यधिक समय, धन और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। गरीबी और संसाधनों की कमी वाले लोगों के लिए यह एक बड़ा बोझ बन जाता है। इलाहाबाद में एक मुकदमे के लिए जाने का मतलब है, न केवल यात्रा का खर्च, बल्कि वहाँ रहने और खाने का भी खर्च। इसके अलावा, वकीलों की फीस भी अधिक होती है। यह सब मिलकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए न्याय को बहुत महंगा बना देता है। एक बात और इलाहाबाद की जगह यदि पश्चिम उत्तर प्रदेश को लखनऊ खंडपीठ से संबद्ध कर दिया जाता, तब भी दूरी दौ सौ किलोमीटर के आसपास कम हो जाती। लखनऊ पश्चिम उत्तर प्रदेश के नजदीक पड़ता है किंतु ऐसा भी नही किया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पहले से ही मुकदमों का भारी बोझ है। पश्चिमी यूपी से आने वाले मामलों की बड़ी संख्या के कारण, न्याय में और अधिक देरी होती है। एक बेंच की स्थापना से मामलों का तेजी से निपटारा हो सकेगा। इससे न्यायपालिका पर दबाव कम होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे अक्सर "भारत का चीनी का कटोरा" कहा जाता एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से इस क्षेत्र की न्यायिक और राजनीतिक पहचान मजबूत होगी, और यह एक आत्मनिर्भर केंद्र बन सकेगा। वर्तमान में भी यह आंदोलन जारी है, हालाँकि इसने कई बार धीमी गति पकड़ी है। 1981 से वकीलों के संगठन नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को हड़ताल करते हैं, वे धरने देते रहतें हैं, और ज्ञापन सौंपते हैं। हालांकि, इस आंदोलन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस आंदोलन के सामने सबसे बडी चुनौती है कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से नहीं लिया है। केंद्र और राज्य सरकारें इस मांग को टालती रही हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वकील इस मांग का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बेंच की स्थापना से उनका काम और आय प्रभावित होगी। सरकार का तर्क है कि एक बेंच की स्थापना से प्रशासनिक जटिलताएँ बढ़ेंगी और यह एक आर्थिक बोझ होगा। इसके अलावा, सरकार अक्सर इस मुद्दे को भविष्य के लिए टाल देती है। एक मजबूत और एकीकृत नेतृत्व की कमी ने इस आंदोलन को कमजोर किया है। अलग-अलग संगठन अपने-अपने तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, जिससे एकता नहीं बन पाती। हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापना के लिए सांसद अरुण गोविल मुखर हो गए हैं। सांसद ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग छह करोड़ आबादी को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में उच्च न्यायालय की चार बेंच हैं। मध्य प्रदेश में दो बेंच हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़े होने के बाद भी यहां उच्च न्यायालय की एक पीठ है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए न्याय प्राप्त करना मुश्किल है। सांसद ने कहा कि यहां बेंच मिलने से कम समय में न्याय मिलेगा और धन की भी बचत होगी।एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना से न केवल पश्चिमी यूपी के लोगों को न्याय तक पहुँचने में आसानी होगी, बल्कि यह पूरे राज्य की न्याय प्रणाली को मजबूत करेगा। यह आवश्यक है कि सरकार, न्यायपालिका और सभी हितधारक मिलकर इस मुद्दे का समाधान निकालें। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में बॉम्बे हाईकोर्ट की एक नई पीठ ओर राज्य में चौथी हाईकोर्ट बेंच के गठन की अधिसूचना एक अगस्त को जैसे ही जारी हुई यूपी के मेरठ में सरगर्मियां बढ़ गईं। "पश्चमि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति" ने तुरंत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चमी यूपी के 22 जिलों के बार अध्यक्षों और महामंत्री के साथ बैठक की. समिति के पदाधिकारियों ने सरकार से सवाल किया कि जब कोल्हापुर में बॉम्बे हाईकोर्ट की चौथी बेंच खुल सकती है तो यूपी के मेरठ में हाईकोर्ट की तीसरी बेंच क्यों नहीं स्थापित हो सकती? मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पश्चिमी यूपी के वकीलों ने चार अगस्त को हड़ताल कर प्रदर्शन किया। मुरादाबाद की सांसद कुंवरानी रूचिवीरा ने भी संसद में हाल ही में पचिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बैंच बनाने की मांग कर चुकी हैं। चांदपुर क्षेत्र के विधायक स्वामी ओमवेश ने भी विधान सभा में ये ही मांग की है। कमोबेश पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधि ये मांग कर चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना का आंदोलन पिछले लगभग 70 साल से जारी है। कब तक जारी रहेगा, यह भी नही कहा जा सकता। इतना जरूर कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आंदोलनकारी वकील अब जनता को पश्चिम में हाईकोर्ट की बैंच बनने के फायदे बताकर जनता और जनप्रतिनिधियों को आंदोलन से जोड़ने में लगे हैं। उनका समर्थन ले रहे हैं। आंदोलन को नया रूप दे रहे हैं। आंदोलन को नया तेवर देने में लगें हैं।

अशोक मधुप
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

विकास का संकल्प : ट्रिपल इंजन से बदलेगी दिल्ली की तस्वीर

लेखक - ललित गर्ग

वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में दिल्ली के लिए 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का प्रावधान केवल एक आर्थिक घोषणा नहीं, बल्कि राजधानी के भविष्य की रूपरेखा है। सड़क, रेल परिवहन, मेट्रो विस्तार, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और पुलिस व्यवस्था जैसे बुनियादी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान यह संकेत देता है कि केंद्र सरकार दिल्ली को एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और आदर्श महानगर के रूप में विकसित करना चाहती है। ऐसे समय में जब दिल्ली की भाजपा सरकार अपना एक वर्ष पूर्ण कर रही है, यह स्वाभाविक है कि बीते वर्ष के कामकाज का मूल्यांकन किया जाए और देखा जाए कि तथाकथित "ट्रिपल इंजन सरकार" का लाभ दिल्लीवासियों को कितना और कैसे मिला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की उपलब्धियों और आगामी संकल्पों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ने न केवल नई योजनाओं की शुरुआत की, बल्कि पूर्ववर्ती सरकारों की लंबित और अधूरी परियोजनाओं को भी गति दी है। 'दिल्ली लखपति बिटिया योजना', मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, अधूरी पड़ी आधारभूत परियोजनाओं को पूरा करने की पहल, तथा महिलाओं और छात्रों के लिए नई राहतकारी योजनाओं का खाका-ये सब उनके पहले वर्ष के प्रमुख बिंदु रहे। उनका यह भी कहना है कि ट्रिपल इंजन की व्यवस्था-अर्थात केंद्र, राज्य और नगर निकाय में एक ही राजनीतिक नेतृत्व के कारण विकास कार्यों में समन्वय और गति दोनों आई है। ट्रिपल इंजन सरकार की अवधारणा का सबसे बड़ा लाभ वित्तीय समन्वय के रूप में सामने आया है। दिल्ली सरकार को अब पूंजीगत व्यय के लिए ऋण अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो रहा है। पहले जहां ब्याज दर 13-14 प्रतिशत तक पहुंच जाती थी, वहीं अब लगभग सात प्रतिशत पर ऋण मिलना संभव हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा 21 हजार करोड़ रुपये तक की ऋण सीमा निर्धारित किए जाने से आधारभूत ढांचे के विकास में धनाभाव की आशंका कम हुई है। यही नहीं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन तथा पीएम भीम योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं की समयावधि बढ़वाने में भी दिल्ली सरकार को सफलता मिली है। आयुष्मान भारत जैसी जनकल्याणकारी योजना का लाभ अब राजधानी के अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंच रहा है, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा की ठोस गारंटी मिल रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के संकेत अवश्य दिखाई दिए हैं। मोहल्ला क्लीनिक मॉडल पर उठे प्रश्नों और अधूरी स्वास्थ्य परियोजनाओं के बीच नई सरकार ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण, बेड क्षमता बढ़ाने और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। यदि यह प्रयास निरंतरता से जारी रहा तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के अनुरूप विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार का दावा किया गया है। पिछले वर्षों में शिक्षा मॉडल को लेकर जहां एक ओर प्रशंसा हुई, वहीं भवनों की गुणवत्ता, संसाधनों के उपयोग और परिणामों पर सवाल भी उठे। नई सरकार के लिए यह चुनौती है कि वह शिक्षा को राजनीतिक विमर्श से ऊपर उठाकर वास्तविक गुणवत्ता सुधार की दिशा में कार्य करे। परिवहन और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी गति लाने का प्रयास हुआ है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, बस बेड़े के आधुनिकीकरण और सड़कों के सुधार की योजनाएं केंद्र और राज्य के समन्वय से आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली मेट्रो पहले से ही राजधानी की जीवनरेखा रही है, अब किराए में राहत या छात्रों के लिए विशेष प्रावधान जैसे कदम यदि लागू होते हैं तो इससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। यातायात जाम की समस्या के समाधान के लिए फ्लाईओवर, अंडरपास और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली पर ध्यान देना आवश्यक है।

इटली को वेस्टइंडीज ने रौंदा, खत्म हुआ वर्ल्डकप में सफर

अब सुपर 8 में नजर आएगी कैरेबियाई टीम शमार, जोसेफ को 4 विकेट

कोलकाता (एजेंसी)। वेस्टइंडीज ने टी-20 वर्ल्डकप के 37वें मुकाबले में इटली को 42 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज की इस वर्ल्डकप में यह लगातार चौथी जीत है। गुरुवार को दिन के पहले मैच में इटली ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 165 रन बनाए हैं। जवाब में इटली 18 ओवर में 123 रन पर ऑलआउट हो गई। ग्रुप-सी का यह आखिरी मुकाबला था।

166 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी इटली के लिए बेन मैनेंटी ने 26, जेजे स्मट्स ने 24, एंथोनी मोस्का ने 19 और ग्रांट स्टीवर्ट ने 12 रन बनाए। बाकी 7 बैटर्स दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। वेस्टइंडीज के लिए शमार जोसेफ ने 4, मैथ्यू फोर्ड ने 3 और गुडाकेश मोती ने 2 विकेट लिए। अकील हुसैन को भी 1 विकेट मिला। वेस्टइंडीज के लिए शाई होप ने अर्धशतक लगाया। उन्होंने 46 बॉल पर 75 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके अलावा, रोस्टन चेज 24 और शेरफेन रदरफोर्ड ने नाबाद 24 रन बनाए। इटली के लिए क्रिशन कलुगमागे और बेन मैनेंटी ने 2-2 विकेट लिए। अली हसन और थॉमस ड्राका को 1-1 विकेट मिला।

मैग्नस कार्लसन बने विश्व फीस्टाइल शतरंज चैम्पियन

वाइजनहाउस ,जर्मनी (एजेंसी)। फ़ीडे फीस्टाइल शतरंज विश्व चैम्पियनशिप 2026 का खिताब दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने अमेरिका के फैबियानो करुआना को 2.5-1.5 से हराकर विश्व चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया। चौथे और अंतिम गेम में ड्रॉ कार्लसन के लिए खिताब सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रहा। निर्णायक क्षण तीसरे गेम में आया, जब कार्लसन लगभग हारी हुई स्थिति से मुकाबला पलटने में सफल रहे। करुआना को तीन अलग-अलग मौकों पर जीत के अवसर मिले, लेकिन समय दबाव और जटिल स्थिति के कारण वे बढ़त को जीत में नहीं बदल सके। तीसरे गेम में बढ़त लेने के बाद कार्लसन ने अंतिम मुकाबले में संतुलित एंडगेम में ड्रॉ कर खिताब अपने नाम कर लिया।

भारत-बीसीसीआई से रिश्ते सुधारना चाहता है बांग्लादेश

● नए खेलमंत्री बोले- पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने की मंशा

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश के नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर अमीनुल हक बीसीसीआई और भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को जल्दी सुलझाना चाहते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के मौजूदा टी-20 वर्ल्ड कप में हिस्सा न लेने का जिक्र किया। हक ने कहा- शपथ लेने के बाद मैं पार्लियामेंट बिल्डिंग में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर से मिला। मैंने उनसे टी-20 वर्ल्ड कप पर बात की। यह एक अच्छी बातचीत थी। मैंने उनसे कहा कि हम इस मुद्दे को बातचीत से जल्दी सुलझाना चाहते हैं क्योंकि हम अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं। इस टी-20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को अपने मुकाबले मुंबई और कोलकाता में खेलने थे। हालांकि, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टीम ने भारत दौरे पर आने से इनकार कर दिया। इसके बाद आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल करने का फैसला किया था।

पूर्व खेल मंत्री आसिफ ने कहा था कि भारत में खिलाड़ियों के सुरक्षा की चिंता- नजरुल- बांग्लादेश सरकार के पूर्व खेल मंत्री आसिफ नजरुल ने नेशनल टीम को भारत भेजने से मना किया था। उन्होंने कहा था, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत में हमारे खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंता है।

● पीएम मोदी ने तारिक रहमान को जीत की बधाई दी थी- इससे पहले 13 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी और रहमान के बीच पहली फोन बातचीत हुई थी। मोदी ने तारिक रहमान को जीत की बधाई दी थी। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए साथ काम करने को उत्सुक हैं। बीएनपी ने एक्स पर एक पोस्ट में मोदी के बधाई संदेश के लिए धन्यवाद दिया। पार्टी ने कहा, 'हम भारत के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़ने को तैयार हैं। हमारा रिश्ता आपसी सम्मान, एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि की साझा प्रतिबद्धता से आगे बढ़ेगा।'

मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने पर विवाद

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के कारण बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने की अनुमति नहीं दी। उन्हें केकेआर ने 3 जनवरी को बीसीसीआई के कहने पर टीम से बाहर कर दिया था। इससे बौखलाई बांग्लादेश सरकार ने अपने यहां आईपीएल मैचों के प्रसारण पर रोक लगा दी। इसके बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देकर 7 फरवरी से होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप में वेन्यू बदलने की मांग भी की।

नामीबिया पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत

वहीं भारत ने लगातार नीदरलैंड को हराकर चौथा मैच जीता

कोलंबो (एजेंसी)। टी-20 वर्ल्ड कप में बुधवार को पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रन से हराकर सुपर-8 स्टेज में एंट्री कर ली। यह टीम की वर्ल्ड कप में रन के अंतर से सबसे बड़ी जीत रही। दूसरी ओर टीम इंडिया ने टूर्नामेंट इतिहास में रिकॉर्ड 12वां लगातार मैच जीत लिया। वहीं टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा लगातार तीसरे मुकाबले में खाता नहीं खोल सके।

पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत- पाकिस्तान ने बुधवार को नामीबिया के खिलाफ 199 रन बनाने के बाद उन्हें 97 रन पर समेट दिया। टीम ने 102 रन से मुकाबला जीता। यह टी-20 वर्ल्ड कप में रन के अंतर से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत रही। इससे पहले 2009 में टीम नीदरलैंड को लॉर्ड्स स्टेडियम में 82 रन से हरा चुकी है।

दुबे की वर्ल्डकप में पहली फिफ्टी, चक्रवर्ती को 3 विकेट

भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार चौथा मैच जीत लिया है। टीम ने बुधवार के तीसरे मैच में नीदरलैंड को 17 रन से हराया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ग्रुप ए के इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन ही बना सकी। शिवम दुबे ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया।

भारत ने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया

नीदरलैंड के खिलाफ टी-20 में भारत ने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। यह एक मुकाबले में भारत की ओर से दूसरे सबसे ज्यादा गेंदबाज रहे। टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ भी 7 ही बॉलर्स से गेंदबाजी कराई थी। भारत इस टूर्नामेंट में 9 कैच छोड़ चुका है, जो आयरलैंड के 10 कैचों के बाद सबसे ज्यादा है। नीदरलैंड ने बगैर फिफ्टी लगाए अपना बेस्ट टी-20 स्कोर बनाए। टीम ने 7 विकेट खोकर 176 रन बनाए। इससे पहले 2018 में टीम ने नेपाल के खिलाफ 174 रन बनाए थे। नीदरलैंड ने टी-20 वर्ल्ड कप में अपना दूसरा बेस्ट स्कोर बनाया। टीम इससे पहले 2014 में आयरलैंड के खिलाफ 13.5 ओवर में ही 193 रन बना चुकी है।

ईशान किशन टी-20

आईसीसी बैटर रैंकिंग के टॉप 10 में

17 पायदान की छलांग लगाई, पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन की आतिशी पारी का फायदा

दुबई (एजेंसी)। आईसीसी ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच ताजा टी-20 रैंकिंग जारी कर दी है। इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन टॉप-10 बैटर्स में शामिल हो गए हैं। उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्डकप में खेली गई 77 रनों की पारी का फायदा मिला।

ईशान 17 पायदान चढ़कर बल्लेबाजों की लिस्ट में 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। लिस्ट में टॉप पर भारत के ही अभिषेक शर्मा हैं। गेंदबाजी में भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती दुनिया के नंबर-1 टी-20 गेंदबाज बने हुए हैं। वहीं, ऑलराउंडर्स की लिस्ट में पाकिस्तान के सईम अयूब एक बार फिर नंबर-1 बन गए हैं।

आउट होने वाले अभिषेक नंबर-1- भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ डक पर आउट होने के बाद भी टी-20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर-1 स्थान पर बने हुए हैं। इंग्लैंड के फिल सॉल्ट दूसरे स्थान पर काबिज हैं। श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज पथुम निसंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैंडी में शानदार शतक जड़कर तीन स्थान की छलांग लगाई और तीसरे नंबर पर पहुंच गए। इंडिया के तिलक वर्मा भी एक पायदान की छलांग लगाते हुए चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं।

पाक बैटर साहिबजादा फरहान को नुकसान- दूसरी तरफ पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान 2 स्थान नीचे लुढ़क गए हैं। साहिबजादा अब 5वें स्थान पर खिसक गए हैं। इंग्लैंड के जोस बटलर को भी तीन स्थान का नुकसान हुआ है और अब वह 7वें पायदान पर खिसक गए हैं।

न्यूजीलैंड के टिम सीफर्ट और ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड को भी एक-एक स्थान का नुकसान हुआ है, बावजूद इसके दोनों बल्लेबाज टॉप-10 में बने हुए हैं। अब सीफर्ट 9वें जबकि हेड 10वें स्थान पर खिसक गए हैं। साहिबजादा फरहान भारत के खिलाफ 15 फरवरी को खेले गए मैच में जीरो पर आउट हुए थे।

व्यापार

गोल्ड-सिल्वर फ्यूचर पर मार्जिन हटाकर एमसीएक्स ने ट्रेडर्स को दिया तोहफा

नई दिल्ली, एजेंसी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के शेयर की कीमत में गुरुवार को कारोबार के दौरान 3.32 प्रतिशत तक का उछाल देखने को मिला। कंपनी ने बुधवार शाम को एक सर्कुलर जारी कर गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर पर लगाए गए अतिरिक्त मार्जिन को हटाने की घोषणा की थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के शेयर की कीमत में गुरुवार को कारोबार के दौरान 3.32 प्रतिशत तक का उछाल देखने को मिला। कंपनी ने बुधवार शाम को एक सर्कुलर जारी कर गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर पर लगाए गए अतिरिक्त मार्जिन को हटाने की घोषणा की थी। इस खबर के बाद एमसीएक्स के शेयर आज एनएसई पर 2,400 रुपये पर खुले। बुधवार के शेयर 2,341 रुपये पर बंद हुए थे। एमसीएक्स ने बुधवार शाम जारी सर्कुलर में कहा कि वह गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर लगा 3 प्रतिशत का अतिरिक्त मार्जिन और सिल्वर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर लगा 7 प्रतिशत का अतिरिक्त मार्जिन वापस ले रहा है। मार्जिन हटाने का यह फैसला गुरुवार, 19 फरवरी से प्रभावी हो गया है। सर्कुलर के अनुसार, गोल्ड फ्यूचर के सभी वेरिएंट और सिल्वर फ्यूचर के सभी वेरिएंट से ये अतिरिक्त मार्जिन हटा लिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर, एनएसई क्लियरिंग ने भी एक सर्कुलर जारी कर गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर पर मार्जिन वापस लिए जाने की पुष्टि की है, जो आज से प्रभावी हो गया है। एनएसई ने अपने सदस्यों को सलाह दी है कि वे अपनी पोजीशन को उसी के अनुसार एडजस्ट करें। इस फैसले से गोल्ड और सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट में कारोबार करने वाले ट्रेडर्स के लिए मार्जिन की आवश्यकता कम हो जाएगी।

टीवीएस मोटर, कोचीन शिपयार्ड समेत 10 शेयरों में हलचल की उम्मीद

नई दिल्ली, एजेंसी। सेबी-रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और लिवलॉन्ग वेल्थ के संस्थापक हरिप्रसाद का मानना है कि भारतीय इक्विटी बाजार आज सपाट से लेकर थोड़ा सकारात्मक रुख के साथ खुल सकता है। यह रुझान निफ्टी के संकेतों से समर्थित है, जो अमेरिकी शेयरों में कल हुई तेजी खासकर टेक्नोलॉजी शेयरों में आई मजबूती और एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों को दर्शाता है।

निफ्टी 50 और सेंसेक्स के निकट भविष्य के परिदृश्य पर बात करते हुए, कोटक सिक्योरिटीज में हेड इक्विटी रिसर्च, श्रीकांत चौहान ने कहा, हमारा मानना है कि अल्पकालिक सपोर्ट 25500/83000 से बढ़कर 25600/83300 हो गया है। जब तक बाजार इस स्तर से ऊपर बना रहता है, तब तक तेजी जारी रहने की संभावना है। ऊपर की ओर, 25950-26000/84700-85000 का स्तर तुरंत रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर सकता है। दूसरी ओर, 25600/83300 के नीचे आने पर रुझान बदल सकता है; इस स्तर से नीचे आने पर कारोबारी अपने ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकलना पसंद कर सकते हैं। कंपनी ने शेयर बाजार को सूचित किया कि उसकी प्रमुख सहायक कंपनी, लाइनएज पावर प्राइवेट लिमिटेड, को सऊदी अरब स्थित याकिन केम से 1.35 मिलियन डॉलर का ऑर्डर मिला है। भारत फोर्ज ने ऐलान किया है कि उसने वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत ऑटोमोटिव और रक्षा सहित कई प्रौद्योगिकी-केंद्रित क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी की संभावना तलाशी जाएगी।

डॉ. रेड्डीज: फार्मा कंपनी डॉ. रेड्डीज ने घोषणा की कि उसने मर्क्यूरी फार्मा ग्रुप लिमिटेड से भारत में प्रोगाइनोवा और साइक्लोप्रोगाइनोवा ट्रेडमार्क और संबंधित संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया है।

एनसीसी: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एनसीसी पर नए ऑर्डर लेने पर रोक लगा दी है।

जिंदल सॉ: अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए ऑडिट के दौरान कुछ मुद्दे पाए जाने के बाद कंपनी का सीमलेस पाइप के लिए एपीआई लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

टाटा स्टील के शेयर ने बनाया नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली, एजेंसी। टाटा स्टील के शेयर में तेजी का सिलसिला जारी है। शेयर मार्केट में आज कमजोरी के बीच कंपनी का शेयर 1 फीसदी की बढ़त के साथ 211.35 रुपये के नए हाई पर पहुंच गया। यह उछाल घरेलू कारोबार को लेकर मजबूत संभावनाओं के चलते आया है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी का शेयर 10 फरवरी, 2026 को बने अपने पिछले रिकॉर्ड 211.15 रुपये को पार कर गया। पिछले एक महीने में टाटा स्टील ने 12 फीसदी की जबरदस्त बढ़त हासिल की है, जबकि इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 0.5 फीसदी और मेटल इंडेक्स में 3.6 फीसदी की मामूली बढ़त हुई है।

क्यों हो रही है टाटा स्टील के शेयर में तेजी टाटा स्टील ने दिसंबर तिमाही (वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही) में मजबूत प्रदर्शन किया है। कंपनी की कुल परिचालन आय सालाना आधार पर 6 फीसदी बढ़कर 57,002 करोड़ रुपये रही। स्टील बिक्री की मात्रा भी 6 फीसदी बढ़कर लगभग 8.2 मिलियन टन रही। हालांकि, कंपनी का ईबीआईटीडीए मार्जिन पिछली तिमाही के मुकाबले 77 आधार अंक गिरकर 14.4 फीसदी रहा, लेकिन आगे की संभावनाएं उज्ज्वल हैं।

कंपनी को उम्मीद है कि चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) में उसका प्रदर्शन बेहतर होगा। इसका मुख्य कारण सेफगार्ड ड्यूटी के कारण कीमतों में 12 फीसदी का सुधार है, जिससे भारत में उसकी बिक्री से होने वाली आमदनी में प्रति टन लगभग 2,300 रुपये का इजाफा होने की संभावना है। इसके अलावा, बेहतर परिचालन लाभ, लागत में लगातार बचत, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का क्रियान्वयन और यूरोप में आयात कोटा प्रतिबंध जैसे कदमों से भी मुनाफे में सुधार होने की उम्मीद है।

करीब एक सदी पुरानी यह कंपनी सरकार की 2030 तक राष्ट्रीय कच्चा स्टील क्षमता 300 मिलियन टन पहुंचाने की योजना के तहत बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता लगभग 40 मिलियन टन प्रति वर्ष करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का मानना है कि टाटा स्टील के शेयर में और तेजी आ सकती है। ब्रोकरेज फर्म ने घरेलू मांग के मजबूत आउटलुक, सेफगार्ड ड्यूटी से कीमतों को मिल रहे सपोर्ट, क्षमता विस्तार और यूरोपीय संघ (ईयू) कारोबार में धीरे-धीरे सुधार के चलते कंपनी पर सकारात्मक रुख अपनाया है। एमओएफएसएल ने सितंबर 2027 के अपने अनुमान के लिए 240 रुपये प्रति शेयर का टार्गेट रखते हुए बाय की सिफारिश की है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि यूरोप में हालांकि निकट भविष्य में मुनाफा स्प्रेड रिकवरी और ऊर्जा लागत पर निर्भर करेगा, लेकिन सीबीएएम और सख्त आयात कोटा जैसे संरचनात्मक उपायों से कीमतों में अनुशासन आएगा और आयात से मार्जिन पर पड़ने वाला दबाव कम होगा। भारत में मजबूत प्रदर्शन और यूरोप में सुधार से कंपनी की कुल कमाई को बल मिलेगा।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का भी कहना है कि सेफगार्ड ड्यूटी से कीमतों में बढ़ोतरी, अनुकूल मांग और रणनीतिक क्षमता विस्तार के कारण टाटा स्टील का भारतीय परिचालन लंबी अवधि में मजबूत वृद्धि के लिए तैयार है।

यूरोप में आयात नियंत्रण के उपायों से नीदरलैंड में कंपनी के संचालन की लाभप्रदता बढ़ने की उम्मीद है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी टाटा स्टील पर रेटिंग बनाए रखी है और संशोधित टार्गेट प्राइस 250 रुपये तय की है।

टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर में तूफानी तेजी

नईदिल्ली, एजेंसी। टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर गुरुवार को बीएसई में 11 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 719 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 साल में टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में 578 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। टाटा ग्रुप की यह दिग्गज कंपनी अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन का मार्केट कैप गुरुवार को 36000 करोड़ रुपये को पार कर गया है।

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) कर चुकी है। कंपनी ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने अक्टूबर 2025 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है। दिसंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 73.38 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 26.62 पर्सेंट है। शेयर पिछले 5 साल में 578 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 19 फरवरी 2021 को 105.59 रुपये पर थे। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर 19 फरवरी 2026 को 719 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 407 पर्सेंट की तूफानी तेजी देखने को मिली है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)